देश को घुसपैठिया मुक्त करने का संकल्प होगा पूरा

सर्व सहकार सर्व साकार

सहकार जागरण

वर्ष : 03 – अंक : 06 – सितंबर 2025

मजबूत हो रहा सहकारिता का बुनियादी ढांचा

करोड़ो किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को मिल रहा सीधा लाभ

एनसीडीसी से मजबूत हो रहीं सहकारी समितियां

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ

अनुक्रमणिका

सर्व सहकार सर्व साकार

सहकार जागरण

सितंबर 2025, अंक 06, वर्ष 03

संपादक मंडल

प्रधान संपादक
डॉ. सुधीर महाजन

संपादक
राजीव शर्मा

समूह संपादक
वेद प्रकाश सेतिया

सहकार जागरण से जुड़ी प्रतिक्रिया, सुझाव या आलेख देना चाहते हैं तो हमें ई-मेल करें :
sahakarjagran@gmail.com
ncui.pub@gmail.com

प्रकाशन का अंतिम निर्णय संपादक मंडल का होगा।

निदेशक (प्रकाशन/जनसंपर्क),
एनसीयूआई
एनसीयूआई कैंपस, 3, अगस्त क्रांति मार्ग, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली : 110016

सहकार जागरण से जुड़ने के अन्य पते :

MINISTRY OF COOPERATION

NCUI हाट

CEAS-LMS

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा 'सहकार जागरण' पत्रिका का सम्पादन एवं प्रकाशन किया जाता है, और इस पत्रिका के प्रकाशन के किसी भी हिस्से की सामग्री की प्रतिलिपि, पुनः उत्पादन या पुनर्वितरण संपादक पैनल और सामग्री के लेखक/लेखकों जैसा भी लागू हो, उनकी लिखित सहमति के बिना कोई भी व्यक्ति, संगठन या पार्टी नहीं कर सकती है। पत्रिका में प्रदर्शित सामग्री तथा आंकड़ें प्राथमिक और अनुषंगी स्रोतों (उद्योग विशेषज्ञ, अनुभवी व्यक्तियों, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार आदि) से लिए गए हैं। पत्रिका में उपलब्ध आंकड़ों और रिपोर्टों के स्रोतों के संबंध में, न तो भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ और न ही इसके कर्मचारी किसी भी त्रुटि के लिए जिम्मेदार हैं और न ही इस संबंध में उनका कोई कानूनी दायित्व है।

आवरण कथा 08

एनसीडीसी से मजबूत हो रहीं सहकारी समितियां

सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से भारत को विकसित देश बनाने में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 'सहकार से समृद्धि' के संकल्प को पूरा करने में एनसीडीसी ने पूरी ताकत झोंक दी है।

14

सीमावर्ती व आंतरिक सुरक्षा को मजबूत कर आतंकवाद, नार्कोटिक्स और साइबर अपराध पर हुआ प्रभावी नियंत्रण

गुजरात ने न केवल सीमावर्ती सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया है, बल्कि आतंकवाद, नार्कोटिक्स, साइबर अपराध जैसे विभिन्न अपराधों पर भी प्रभावी रूप से अंकुश लगाया है।

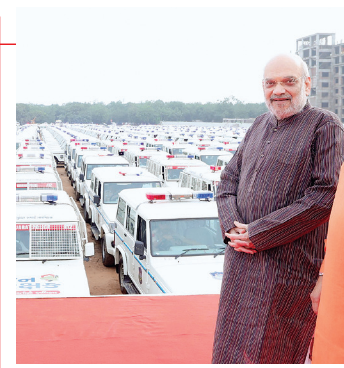

आत्मनिर्भर बेटियां राष्ट्र निर्माण में निभाएंगी महत्वपूर्ण भूमिका 16

बिहार के बेटे बेटियों को राज्य के भीतर ही मिलेगा रोजगार 20

मोदी सरकार में पूर्वोत्तर राज्यों का हुआ अभूतपूर्व विकास 21

विकसित भारत की आधारशिला है आत्मनिर्भर भारत 22

राष्ट्रहित के विचार से ही लोकतंत्र को मिलेगी सर्वोच्च गरिमामयी ऊंचाई 24

माताओं की गरिमा, गौरव व सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता : पीएम मोदी 26

27

जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है मोदी सरकार

समितियों की सामर्थ्य बढ़ा रहा एनसीडीसी

सहकारी समितियां सहकारिता की धुरी हैं। ग्रामीण भारत के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक फैली ये समितियां ही लघु एवं सीमांत किसानों को सहयोग के माध्यम से आत्मनिर्भरता और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाती हैं। इन समितियों को आर्थिक एवं कारोबारी रूप से सक्षम और बहुपयोगी बनाने में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। यह देश के आठ लाख से अधिक सहकारी समितियों को ऋण देकर इन समितियों के 29 करोड़ सदस्यों के जीवन को समुन्नत बनाने में योगदान कर रहा है। इन सदस्यों में से करीब 94 प्रतिशत किसान ही हैं। एनसीडीसी के आर्थिक सहयोग से सहकारी संस्थाओं को न सिर्फ अपने कारोबार का विस्तार करने में मदद मिल रही है, जिससे समितियों से जुड़े किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।

एनसीडीसी सहकारी कृषि ऋण समितियों (पैक्स), डेयरी सहकारी समितियों और अन्य ग्रामीण विकास संगठनों सहित सभी सहकारी समितियों को विभिन्न विकास गतिविधियों के लिए ऋण, अनुदान और वित्तीय सहायता प्रदान करके सहकारी सदस्यों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करता है। यह कृषि उपज, खाद्य पदार्थों, औद्योगिक वस्तुओं, पशुओं और अन्य मान्यता प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं के लिए सहकारी उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण और निर्यात को बढ़ावा देकर सहकारी क्षेत्र को मजबूत कर रहा है। एनसीडीसी का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसान सहकारी समितियों को बेहतर बनाने और विकसित करने में मदद करना है। इसके साथ ही यह समितियों को फसल-उपरांत सुविधाएं भी प्रदान करता है। एनसीडीसी का यह प्रयास सहकार से समृद्धि के ध्येय को पूरा करने और विकसित भारत के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है।

एनसीडीसी कृषि क्षेत्र में कार्यरत सहकारी समितियों को वित्तपोषित करके भारत में कृषि विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कृषि आदानों की खरीद, भंडारण, विपणन और प्रसंस्करण हेतु बुनियादी ढाँचे के विकास और कृषि-आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए धन उपलब्ध कराता है। अपनी वित्तीय सहायता के माध्यम से, एनसीडीसी किसान सहकारी समितियों को अपने कार्यों का आधुनिकीकरण करने, उत्पादन क्षमता बढ़ाने और अपने उत्पादों के लिए बेहतर बाजारों तक पहुँच बनाने में मदद करता है। यह स्थायी कृषि पद्धतियों का भी समर्थन करता है और बिचौलियों पर निर्भरता कम करने वाले सहकारी मॉडलों को बढ़ावा देकर किसानों को सशक्त बनाता है।

गैर-कृषि क्षेत्र में एनसीडीसी का प्रयास सहकारी समितियों को आय-उत्पादक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सुविधाएं प्रदान करना है, जिसमें डेयरी, पशुधन, हथकरघा, रेशम उत्पादन, मुर्गीपालन, मत्स्यपालन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, महिला सहकारी समितियों आदि जैसे कमजोर वर्गों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। यह निगम कृषि उत्पादों के साथ-साथ कीटनाशक, उर्वरक, कृषि मशीनरी, साबुन, वस्त्र और रबर जैसी विशिष्ट वस्तुओं के लिए कार्यक्रम संचालित करता है। सहकारी समितियों के माध्यम से यह लघु वन उपज का संग्रहण, प्रसंस्करण, भंडारण, व्यापार और निर्यात भी करता है। एनसीडीसी डेयरी, पोल्ट्री, रेशम उत्पादन, मत्स्य पालन और हथकरघा के अलावा, एनसीडीसी आय-उत्पादक उद्यमों में भी संलग्न है। यह राज्य सरकारों को ऋण और अनुदान भी प्रदान करता है, साथ ही बहु-राज्य कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय स्तर और अन्य समितियों को भी ऋण और अनुदान प्रदान करता है।

जय सहकार

हमारे नौजवान साथियों के लिए इस स्वतंत्रता दिवस का उपहार है- प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। इससे उनके लिए कई सेक्टर्स में रोजगार के नए अवसर बनने वाले हैं।पिछले 11 वर्षों में उद्यमशीलता हमारी बहुत बड़ी ताकत बनी है। आज टियर-2 और टियर-3 सिटी के लाखों युवा भी देश की इकोनॉमी को आगे ले जाने में जुटे हैं। स्टार्ट-अप और स्पेस सेक्टर से लेकर स्पोर्ट्स तक देश की विकास यात्रा में हमारी बेटियां अहम भागीदारी निभा रही हैं। नारीशक्ति को इससे एक सशक्त पहचान मिली है।

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

11 वर्ष पूर्व गरीबों, महिलाओं, किसानों, वंचितों के वित्तीय समावेशन हेतु मोदी जी ने विश्व इतिहास की सबसे बड़ी बैंकिंग पहल 'प्रधानमंत्री जन धन योजना' की शुरुआत की। देश के उस बड़े तबके को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य हुआ, जो दशकों से इससे वंचित रहा था।आज 56 करोड़ से अधिक जन धन लाभार्थी, जिनमें लगभग 56% महिलाएं हैं, बैंकिंग, बीमा, पेंशन जैसी अनेक सरकारी योजनाओं का सीधे लाभ प्राप्त कर रहे हैं और विकसित व आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने में जुटे हुए हैं।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

आत्मनिर्भर कृषि की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए मोदी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को स्वीकृति दी गई। 2025 से 6 साल तक के लिए लागू होगी योजना, इस पर हर वर्ष ₹24,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे और इससे 100 जिलों के 1.7 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।

श्री कृष्ण पाल गूर्जर
केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री

ग्राम स्तर पर कार्यरत पंचायतें और सहकारी समितियां ग्राम विकास का शक्ति केन्द्र हैं। इन दोनों के समन्वय से कार्य करने से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी का सहकार से समृद्धि का संकल्प शीघ्रातिशीघ्र साकार होगा, कृषि और ग्राम विकास परिषद् के माध्यम से यह कार्य शुरु कर दिया है।

श्री दिलीप संघाणी
अध्यक्ष, एनसीयूआई एवं इफको

सहकारी नेतृत्व में 'श्वेत क्रांति 2.0' एक सशक्त और दूरदर्शी विजन के साथ आगे बढ़ रही है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2028-29 तक दुग्ध संग्रहण में 50% की वृद्धि करना है। इस पहल के तहत सहकारी कवरेज का विस्तार दूरस्थ और वंचित क्षेत्रों तक किया जाएगा, साथ ही सतत और सर्कुलर प्रक्रियाओं को अपनाकर पर्यावरण-सम्मत एवं दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित किया जाएगा।

सहकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

मन की बात का 125वां एपिसोड

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'वोकल फार लोकल' का दिया मंत्र

सहकार जागरण टीम

गर्व से कहो 'ये स्वदेशी है'। एक ही मंत्र 'वोकल फार लोकल', एक ही रास्ता 'आत्मनिर्भर भारत', एक ही लक्ष्य 'विकसित भारत'। इस भाव को लेकर हमें आगे चलना है। यह विचार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने मासिक कार्यक्रम 'मन की बात' में व्यक्त किया। देश-भर में 'गणेश उत्सव' का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में बहुत सारे त्योहारों की रौनक होगी। इन त्योहारों में आपको स्वदेशी की बात कभी भी भूलनी नहीं है। उपहार वही जो भारत में बना हो, पहनावा वही जो भारत में बुना हो, सजावट वही जो भारत में बने सामान से हो, रौशनी वही जो भारत में बनी झालरों से हो - और भी ऐसा बहुत कुछ, जीवन की हर जरूरत में सब कुछ स्वदेशी हो।

- **स्वदेशी व आत्मनिर्भरता विकसित भारत का आधार**
- **सौर-ऊर्जा सिर्फ बिजली का साधन नहीं, बल्कि ये गांव-गांव में नई रोशनी लाने वाली एक नई शक्ति भी**

विकसित भारत के लिए स्वदेशी व आत्मनिर्भरता को एक प्रमुख मार्ग बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न वस्तुओं के उत्पादकों से विनती है कि आप सामानों की क्वालिटी सुधारें, उसकी कीमत घटाएं, आप देखना हिंदुस्तान का आदमी कभी बाहर से कुछ नहीं लेगा। यह भाव हम जगाएं और दुनिया के सामने उदाहरण पेश करें।

मॉनसून में देश में जारी प्राकृतिक आपदा और इससे हो रही जन-धन हानि पर प्रधानमंत्री ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि पीड़ितों को बचाने के लिए एनडीआरएफ-एसडीआरएफ व अन्य सुरक्षा बलों के जवान दिन-रात जुटे रहे। उन्होंने तकनीक का सहारा भी लिया। ऐसे अनेक आधुनिक संसाधनों के सहारे राहत कार्य में तेजी लाने की भरपूर कोशिश की गई। इस दौरान हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाई गई, घायलों को एयरलिफ्ट किया गया। आपदा की घड़ी में सेना मददगार बनकर सामने आई। स्थानीय लोगों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, डॉक्टरों समेत संकट की इस घड़ी में मानवयीता को सबसे ऊपर रखने वालों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं।

जम्मू-कश्मीर में खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए श्री मोदी ने इसके लिए जम्मू-कश्मीर की सरकार और वहां की जनता की आत्मीयता और मेहमाननवाजी की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

सिविल सेवा की परीक्षा में अंतिम सूची में स्थान बना पाने में असफल उम्मीदवारों के लिए 'प्रतिभा सेतु' नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए जाने का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे दस हजार से ज्यादा होनहारों की जानकारी 'प्रतिभा सेतु' पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। निजी कंपनियां इस पोर्टल से जानकारी लेकर उन्हें अपने यहां नियुक्ति दे सकती हैं। इस प्रयास के नतीजे भी आने लगे हैं।

सौर ऊर्जा की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सोलर पावर से किसानों की जिंदगी बदल रही है। इससे किसानों को उनकी मेहनत का फल ज्यादा मिल रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रतनपुरा गांव की रहने वाली देवकी जी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हेंने सोलर पंप से गांव की किस्मत बदल दी। लोग अब प्यार से उन्हें 'सोलर दीदी' कहते हैं। उनकी मेहनत और दूरदर्शिता ने दिखा दिया है कि सौर-ऊर्जा सिर्फ बिजली का साधन नहीं है, बल्कि ये गांव-गांव में नई रोशनी लाने वाली एक नई शक्ति भी है।

स्वच्छता पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि जहां स्वच्छता है, वहां आनंद है, स्वास्थ्य है, समृद्धि है। इसलिए सभी को साफ-सफाई का और पर्यावरण की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। ■

गुजरात के राजकोट में सहकारी समितियों की वार्षिक बैठक में बोले श्री अमित शाह

मजबूत हो रहा सहकारिता का बुनियादी ढांचा

सहकार जागरण टीम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता गांव-गांव में समृद्धि लाने का मजबूत माध्यम बन रही है और सहकारी क्षेत्र दिन-दूनी, रात-चौगुनी प्रगति कर रहा है। नई सहकारिता नीति, मॉडल बायलॉज, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी, श्वेत क्रांति 2.0 जैसी पहलों से सहकारिता जहां नए युग के अनुकूल हो रही है, वहीं अन्न भंडारण योजना और तीन राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियों की स्थापना से किसानों के उत्पाद वैश्विक बाजार तक पहुंच रहे हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इन उपलब्धियों को गुजरात के राजकोट में जिला सहकारी बैंक लिमिटेड सहित सात जिला स्तरीय सहकारी समितियों की वार्षिक बैठक के दौरान साझा किया। उन्होंने कहा कि अब देश के कोने-कोने में नई सहकारी समितियां, नए दूध संघ और किसानों के दूध को प्रसंस्करण कर मुनाफा अर्जित करने वाली समितियां स्थापित हो रही हैं। इनके माध्यम से किसानों को मुनाफा वापस देने की कंप्यूटरीकृत व्यवस्था गुजरात सहित पूरे भारत में लागू की गई है। श्री शाह ने कहा कि गुजरात में सहकारी क्षेत्र के तहत सभी सहकारी संस्थाओं को जिला सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक से ही ऋण देने की व्यवस्था बनाई गई है। बनासकांठा और पंचमहल में इस व्यवस्था के सफल प्रयोग के बाद अब इसे पूरे गुजरात में लागू किया जा रहा है।

- **सहकारी सफलता की मिसाल है राजकोट का सहकारी क्षेत्र**
- **करोड़ों किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को उनका मुनाफा सीधा बैंक खाते में हो रहा जमा**
- **दशकों से कमजोर सहकारी तंत्र 12 प्रतिशत वृद्धि के साथ मजबूत हुआ है**

सहकारी सफलता की मिसाल है राजकोट का सहकारी क्षेत्र

श्री शाह ने कहा कि राजकोट का सहकारी क्षेत्र न केवल गुजरात, बल्कि पूरे देश के लिए सहकारी सफलता का एक उदाहरण है।

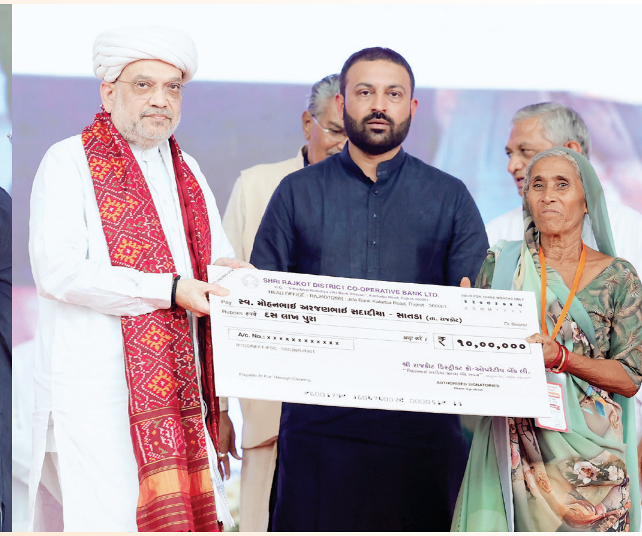

उन्होंने सहकारी क्षेत्र को और मजबूत किए जाने पर जोर देते हुए देश के प्रत्येक गांव में दूध मंडली, सेवा सहकारी मंडली और गोदाम युक्त सहकारी समितियों की स्थापना की प्रेरणा दी। श्री शाह ने कहा कि किसी सहकारी संस्था का परिचय यही होता है कि उसका मुनाफा किसान के हितों के लिए उपयोग हो। राजकोट जिला सहकारी बैंक को पांच बार नाबार्ड का बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड और चार बार ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड प्राप्त हुआ है। यह जिले के किसानों की मेहनत और राजकोट जिला सहकारी बैंक के सभी डायरेक्टर्स व अध्यक्ष के कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है। उन्होंने कहा कि 53 वर्षों तक लगातार ऑडिट में एक प्रतिशत से भी कम नेट एनपीए, सैकड़ों करोड़ रुपए का मुनाफा और शून्य ब्याज दर पर ऋण देने के बाद भी राजकोट जिला सहकारी बैंक अपनी मजबूत व्यवस्था को कायम रखने में सफल हुआ है।

सहकारी क्षेत्र में नई शुरुआतों का किसानों को मिल रहा लाभ

श्री शाह ने कहा कि सहकारी क्षेत्र में कई नई शुरुआत किए गए हैं। किसानों को उनके जैविक उत्पादों का पूरा मुनाफा मिले, इसके लिए 'भारत ऑर्गेनिक' नामक सहकारी संस्था की स्थापना की गई, जो किसानों से जैविक सामान खरीदकर बेचती है और सारा मुनाफा किसानों को वापस देती है। इसके अतिरिक्त सहकारी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिलेट (एनसीईएल) और बीज विकास के लिए भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिलेट (बीबीएसएसएल) मानक नई सहकारी संस्थाएं बनाई गई हैं।

किसानों से रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का उपयोग कम करने और जैविक खेती को अपनाने की अपील करते हुए श्री शाह ने कहा कि इससे न केवल देश के लोगों का स्वास्थ्य सुधरेगा, बल्कि किसानों को अधिक मुनाफा भी मिलेगा। सौराष्ट्र के सभी किसानों को जैविक खेती की दिशा में आगे बढ़ने की अपील करते हुए उन्हें वैश्विक जैविक उत्पाद बाजार में भारत का हिस्सा बढ़ाने में योगदान को प्रेरित किया। श्री शाह ने कहा कि भारत सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि जैविक खेती करने वाले किसानों को उनके पैदावार का बड़ा लाभ मिले।

सहकारिता मंत्रालय के गठन ने बदली तस्वीर

श्री शाह ने कहा कि देश की आजादी के बाद से ही सहकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की मांग थी कि केंद्र सरकार में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया जाए। लेकिन, देश के विशाल सहकारी तंत्र को कृषि मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव द्वारा संचालित किया जाता था। इससे सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा था। ऐसे में, प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वर्ष 2021 में में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना करके सहकारी विकास के द्वार खोल दिए। श्री शाह ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामाख्या तक पूरे देश में करोड़ों किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को ऐसा अवसर मिला है कि उनकी मेहनत से प्राप्त मुनाफा सीधा उनके बैंक खाते में जा रहा है।

श्री शाह ने राजकोट में सरदार वल्लभभाई पटेल और विठ्ठलभाई रादडिया की प्रतिमाओं का अनावरण भी किया। उन्होंने कहा कि वल्लभभाई पटेल ने न केवल राजकोट, बल्कि पूरे देश के किसानों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी, राजकोट जिला कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की, उसे मजबूती प्रदान की और उसे विस्तार प्रदान किया। वहीं, विठ्ठलभाई ने लंबे समय तक इस बैंक की सेवा की और इसे नाबार्ड के अनेक अवार्ड जीतने वाली बैंक में परिवर्तित कर किया। श्री शाह ने बैंक की दुर्घटना बीमा योजना के तहत 22 लोगों को और बैंक के कृषि समाज पुरस्कार के तहत नौ सहकारी समितियों को मोटरसाइकिल और मुआवजा भी प्रदान किया। साथ ही, आरडीसी बैंक की दुर्घटना बीमा योजना, मेडिकल सहायता योजना और कृषि समाज पुरस्कार योजना के तहत लाभ वितरण भी किया। ■

एनसीडीसी से मजबूत हो रहीं सहकारी समितियां

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने वित्त वर्ष 2024-25 में सहकारी समितियों को 95 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का दिया वित्तीय प्रोत्साहन

सहकार जागरण टीम

सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से भारत को विकसित देश बनाने में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के संकल्प को पूरा करने में एनसीडीसी ने पूरी ताकत झोंक दी है। एनसीडीसी देश भर की सहकारी संस्थाओं को वित्तीय मदद पहुंचाती है। इसके माध्यम से सहकारिता की निचली

- **मार्केटिंग क्षेत्र की कोऑपरेटिव सोसाइटियों को किसानों से एमएसपी पर उपज की खरीद के लिए मिले 77,942.72 करोड़ रुपए**
- **एनसीडीसी के कदम से राज्यों और सहकारी संस्थाओं को कृषि, सहकारिता और ग्रामीण विकास क्षेत्रों में निवेश और विस्तार के लिए मजबूती मिली**

> एनसीडीसी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में 10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन को बढ़ावा देने वाली कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में काम कर रही है। यह नई सहकारी समितियों का पंजीकरण और उन्हें समर्थन प्रदान करती है। एनसीडीसी प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत मछली किसान उत्पादक संगठन के गठन और संवर्धन के लिए एक कार्यान्वयन एजेंसी भी है।
>
> - श्री अमित शाह
> केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

कृषि उत्पादों की खरीद को भरपूर मदद

ग्रामीण क्षेत्रों की वित्तीय स्थिति में सुधार और किसानों की आमदनी बढ़ाने के मद्देनजर सहकारिता मंत्रालय कृषि उत्पादों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सरकारी खरीद और बाजार में उनकी उपज के बेहतर मूल्य दिलाने के लिए विशेष पूंजी का बंदोबस्त करता है। भारत सरकार रबी और खरीफ सीजन की 24 फसलों की एमएसपी और गन्ने की उचित व लाभकारी मूल्य (एफआरपी) के साथ तीन अन्य कमर्शियल फसलों की एमएसपी की घोषणा करती है। विभिन्न राज्यों की कृषि मंडियों में उपज की कीमतें नीचे होने की दशा में एमएसपी पर सरकारी खरीद शुरू की जाती है। इसके लिए सरकार की विभिन्न एजेंसियों के अलावा कोऑपरेटिव मार्केटिंग एजेंसियां भी बाजार में खरीद करने उतरती हैं। कोऑपरेटिव एजेंसियों के लिए कार्यशील पूंजी का एनसीडीसी प्रबंध करता है। एनसीडीसी ने किसानों की चुनौतियों के समाधान के लिए एमएसपी पर होने वाली उनकी उपज की खरीद के बाबत विभिन्न राज्यों में सहकारी मार्केटिंग सोसाइटियों को वर्ष 2024-25 में 77,942.72 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। जबकि चालू वित्त वर्ष 2025-26 में 30 जून तक इन्हें फसलों की खरीद के लिए 25,984.83 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं।

इकाई पैक्स से लेकर शीर्ष इकाई अपेक्स तक को भरपूर वित्तीय मदद मुहैया कराई जा रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने वर्ष 2023 में एनसीडीसी को तीन वर्ष में सहकारिता क्षेत्र को सालाना एक लाख करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने का लक्ष्य दिया था जिसे समय से पहले ही लगभग पूरा कर लिया गया है।

लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में श्री अमित शाह ने बताया कि एनसीडीसी ने वित्त वर्ष 2024-25 में सहकारी संस्थाओं को 95,182.84 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया है। इनमें सबसे ज्यादा 77,942.72 करोड़ रुपए की मदद मार्केटिंग क्षेत्र में सक्रिय कोऑपरेटिव सोसाइटियों को दिए गए हैं। चालू वित्त वर्ष 2025-26 में 30 जून तक तीन महीने में ही एनसीडीसी ने 26,425.75 करोड़ रुपए के ऋण वितरित कर दिए हैं। इससे सहकारी संस्थाओं को न सिर्फ अपने कारोबार का विस्तार करने में मदद मिल रही है, बल्कि ये संस्थाएं आर्थिक रूप से सशक्त भी हो रही हैं।

पिछला लक्ष्य हासिल होने के साथ ही एनसीडीसी ने अब अगले पांच वर्षों के लिए नया महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है, जिसके तहत वित्तीय सहायता को 2 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाएगा। इस रणनीति के केंद्र में वह सहकारी समितियां हैं जो अब तक हाशिए पर रही हैं, जैसे मत्स्य पालन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की पहाड़ी समितियां, हथकरघा, डेयरी, कुक्कुट पालन और महिला श्रमिक समितियां। यह कदम सहकारिता क्षेत्र में समावेशी और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने में सहकारी संस्थाओं की हिस्सेदारी अहम होगी। इसी के मद्देनजर श्री अमित शाह ने वर्ष 2021 में सहकारिता मंत्रालय की बागडोर संभालते ही इस दिशा में पूरी शिद्दत से प्रयास शुरू कर दिया। एनसीडीसी ने पिछले चार वित्तीय वर्षों में कुल 1,621 ऋण आवेदन स्वीकृत कर राशि वितरित की, जिनकी कुल राशि लगभग 2,31,053.79 करोड़ रुपए है। किसानों की माली हालत में सुधार को प्रतिबद्ध सहकारिता मंत्रालय कृषि ऋण की सहकारिताओं को उच्च प्राथमिकता देता है। देश की 8 लाख से ज्यादा प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी (पैक्स), प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को एनसीडीसी से ही रियायती दरों पर ऋण प्राप्त होता है।

एनसीडीसी के इस कदम से राज्यों और सहकारी संस्थाओं को कृषि, सहकारिता और ग्रामीण विकास क्षेत्रों में निवेश और विस्तार के लिए मजबूती मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में हुए विकास से देश की अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूती मिल रही है। रोजगार के साधन बढ़े हैं। सुनिश्चित खाद्यान्न आपूर्ति से महंगाई पर पर काबू पाने में मदद मिली है। किसानों की उपज की खरीद, भंडारण और वितरण क्षेत्र में सहकारी समितियों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। शहरी क्षेत्रों में अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को मिली सहूलियत से उनके कारोबार में वृद्धि हुई है।

सहकारिता क्षेत्र की लघु से लेकर वृहद संस्थाओं को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने की दिशा में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उनकी नजर उन 60 करोड़ लोगों पर है जो पूंजी की कमी से जूझ रहे हैं। सहकारिता मंत्री के नेतृत्व में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) उन्हें वित्तीय मदद मुहैया कराने में अहम भूमिका निभा रहा है। उनकी नजर उन गरीब और कम आय वर्ग के लोगों पर है जो पूंजी की कमी से जूझ रहे हैं। सहकारिता मंत्री श्री शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार सहकारी समितियों को मजबूत बनाकर देश के गरीब, वंचित और पिछड़े लोगों को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2021 में गठित सहकारिता मंत्रालय ने देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को मजबूत करने पर सरकार का विशेष ध्यान है।

एनसीडीसी का बढ़ता दायरा

सहकारिता क्षेत्र के विकास में मदद करने में एनसीडीसी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की कार्यान्वयन एजेंसी है। एनसीडीसी सहकारी समितियों को लाभ पहुंचाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। समाज की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसने अपना दायरा बढ़ाया है। कृषि विपणन एवं निवेश, प्रसंस्करण और भंडारण क्षेत्रों को सहायता देने और देश में युवाओं की आय को बढ़ावा देने के लिए सार्थक कदम उठाने से एनसीडीसी का दायरा व्यापक हो गया है। देश में इस समय 8 लाख से अधिक सहकारी समितियां हैं जिनके 29 करोड़ किसान सदस्य हैं। 1963 में अपनी स्थापना के बाद से एनसीडीसी कृषि और बागवानी सहकारी समितियों सहित अन्य सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। एनसीडीसी की क्षमता को पहचानते हुए इसे सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य भंडारण योजना के तहत परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। यह 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और संवर्धन के लिए सहयोग के साथ ही एफपीओ के रूप में नई सहकारी समितियों का पंजीकरण और उन्हें समर्थन प्रदान करती है। निर्यात, जैविक और बीज उत्पादन पर गठित तीन राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियों को बढ़ावा देने पर भी एनसीडीसी ध्यान केंद्रित कर रहा है।

छत्तीसगढ़ को सबसे ज्यादा 535 ऋण आवंटन

एनसीडीसी से ऋण प्राप्त करने में छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पंजाब की सहकारी संस्थाएं अव्वल रही हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में एनसीडीसी ने 535 ऋण आवेदन स्वीकृत कर राशि वितरित की, जिनकी कुल राशि 95,182.84 करोड़ रुपए है। इस दौरान एनसीडीसी के प्रमुख लाभार्थी राज्यों में छत्तीसगढ़ नंबर एक पर रहा है जहां की सहकारी संस्थाओं को 28,080 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पर रहे तेलंगाना को 20,980.07 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश में 16,330 करोड़ रुपए और पंजाब की सहकारी समितियों को 5,702 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद दी गई है। इनके अलावा नैफेड और एनसीसीएफ जैसी राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष सहकारी संस्थाओं को भी आर्थिक सहायता मिली है। इस वित्त वर्ष में नैफेड को 97 करोड़ रुपए और एनसीसीएफ को 1,119.36 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है।

कोऑपरेटिव बैंकों को मिले 42,000 करोड़ रुपए

संसद के मानसून सत्र में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई एक जानकारी में बताया गया कि वित्त वर्ष 2024-25 में एनसीडीसी और नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) ने मिलकर कोऑपरेटिव बैंकों को 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की। एनसीडीसी की ओर से इस अवधि में आंध्र प्रदेश (3,730 करोड़ रुपए) और तेलंगाना (2,000 करोड़ रुपए) के कोऑपरेटिव बैंकों को सबसे ज्यादा आर्थिक मदद दी गई, जबकि मध्य प्रदेश (291 करोड़ रुपए) और राजस्थान (77 करोड़ रुपए)

को भी वित्तीय सहयोग मिला। इसी तरह, नाबार्ड के वितरण में मध्य प्रदेश को सबसे अधिक 4,430 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। इसके बाद ओडिशा (4,113 करोड़ रुपए) और कर्नाटक (3,655.52 करोड़ रुपए) को लाभ मिला। नाबार्ड के अन्य प्रमुख आवंटनों में तमिलनाडु (2,946.49 करोड़ रुपए), राजस्थान (2,760.75 करोड़ रुपए), आंध्र प्रदेश (2,716.55 करोड़ रुपए), महाराष्ट्र (2,696.26 करोड़ रुपए) और गुजरात (1,691.31 करोड़ रुपए) शामिल हैं। छोटे राज्यों में सिक्किम (3.10 करोड़ रुपए), गोवा (23.97 करोड़ रुपए), नागालैंड (33 करोड़ रुपए), मिजोरम (12.60 करोड़ रुपए) और मणिपुर (7.81 करोड़ रुपए) के कोऑपरेटिव बैंकों को भी धनराशि आवंटित की गई। 31 मार्च, 2025 तक देश में 34 राज्य सहकारी बैंक, 352 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और 1,457 शहरी सहकारी बैंक कार्यरत थे। वित्तीय प्रवाह और डिजिटल एकीकरण के साथ सहकारी बैंकिंग क्षेत्र आने वाले वर्षों में ग्रामीण विकास और वित्तीय समावेशन में और अधिक प्रभावी भूमिका निभाएगा।

2,31,053.79 करोड़ रुपए चार वित्त वर्ष में सहकारी समितियों को मिले

2,00,000 करोड़ रुपए सालाना प्रोत्साहन का रखा गया है नया लक्ष्य

1,00,000 करोड़ रुपए सालाना देने का लक्ष्य समय से पहले हुआ पूरा

केंद्रीय अनुदान सहायता

सहकारी समितियों की नई परियोजनाओं को स्थापित करने, उनके संयंत्रों का विस्तार करने और उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने एनसीडीसी को केंद्रीय अनुदान सहायता योजना के तहत 2,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का प्रावधान किया है। वित्त वर्ष 2025-26 से 2028-29 तक की इस योजना के तहत प्रत्येक वित्त वर्ष में एनसीडीसी को 500 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता दी जाएगी। इस अनुदान सहायता के आधार पर एनसीडीसी चार वर्ष की अवधि में खुले बाजार से 20,000 करोड़ रुपए जुटा सकेगी, जिसका उपयोग सहकारी समितियों की वित्तीय सहायता के रूप में की जाएगी। इसके माध्यम से देश भर में डेयरी, पशुधन, मत्स्य पालन, चीनी, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण

अन्न भंडारण और खाद्यान्न प्रसंस्करण

सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से सहकारी समितियों के विकास के लिए 100 से अधिक पहलें हुई हैं। केंद्र सरकार ने सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से विश्व की सबसे बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना शुरू की है, जिस पर एक लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी। गोदामों का निर्माण करने, खाद्यान का भंडारण, विपणन और प्रसंस्करण का दायित्व प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स) को सौंपा गया है। इसके तहत 7 करोड़ टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता विकसित की जा रही है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता वाली अंतर मंत्रालयी समिति की देखरेख में यह योजना काम कर रही है, जिसका बड़ा दायित्व एनसीडीसी को सौंपा गया है। एनसीडीसी ही इस योजना को वित्तीय मदद मुहैया करा रहा है। इसी तरह खाद्यान्न प्रसंस्करण क्षेत्र में काम कर रही सहकारी क्षेत्र की चावल, दाल, गेहूं व मक्का आटा मिलों और पशुचारा इकाइयों को एनसीडीसी से वित्तीय आवंटन के साथ अनुदान प्राप्त हो रहा है। बागवानी फसलों में फल-फूल और मसालों के साथ अन्य कमर्शियल उपज की प्रसंस्करण इकाइयों की पूंजी की जरूरतें भी यहीं से पूरी की जाती हैं। इन फसलों की उपज की निर्यात में बड़ी भागीदारी होने की वजह से सहकारिता मंत्रालय का जोर इस पर ज्यादा है।

और कोल्ड स्टोरेज जैसे विभिन्न क्षेत्रों की 13,288 सहकारी समितियां और श्रमिकों एवं महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समितियों के लगभग 2.90 करोड़ सदस्य लाभान्वित होंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक योगदान देने वाली इन समितियों के लिए दीर्घकालिक और कार्यशील पूंजी ऋण सहयोग आवश्यक है। सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक उत्थान के अलावा आधारभूत ढांचे विकसित करने और रोजगार उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

2,000 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता से सहकारी संस्थाओं को नए प्रोजेक्ट शुरू करने, संयंत्रों के विस्तार तथा ऋण देने में सहायता मिलेगी। इससे सहकारिता से जुड़े करोड़ों सदस्य लाभान्वित होंगे, महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। अनुदान सहायता योजना के तहत एनसीडीसी परियोजना धनराशि का वितरण, अनुवर्ती कार्रवाई, परियोजना निगरानी और निधि से वितरित ऋण की वसूली करेगी। एनसीडीसी सहकारी समितियों को राज्य सरकार के माध्यम से या सीधे ऋण प्रदान करेगी। एनसीडीसी द्वारा सहकारी समितियों को दी गई धनराशि से आय उत्पन्न करने वाली पूंजीगत परिसंपत्तियां सृजित होंगी और सहकारी समितियों को आवश्यक कार्यशील पूंजी तरलता प्राप्त होगी। इससे उन्हें अपनी क्षमता बढ़ाने, आधुनिकीकरण करने, विविध गतिविधियां संचालित करने, उत्पादकता और लाभ बढ़ाने तथा अधिक रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी। इससे सदस्य किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इसके अलावा बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सावधि ऋण, विभिन्न कौशल कार्यबलों में रोजगार के व्यापक अवसर भी उत्पन्न होंगे।

सहकारी चीनी मिलों को बड़ा पैकेज

सहकारिता मंत्रालय एनसीडीसी के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को विशेष प्रोत्साहन

> अमृत काल में गांवों और किसानों के विकास में सहकारी क्षेत्र की भूमिका बड़ी होने वाली है। सरकार और सहकार मिलकर विकसित भारत के सपने को दोगुनी ताकत प्रदान करेंगे। डिजिटल इंडिया अभियान के माध्यम से सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाई और लाभार्थियों के लिए लाभ सुनिश्चित किया। सहकारिता क्षेत्र को आज पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का मॉडल बनाना है। इसके लिए सहकारी क्षेत्र में डिजिटल प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
>
> -श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

देता है। चीनी उद्योग और उससे जुड़े उद्योगों और कोजेनरेशन इकाइयों, कताई मिलों, कपास जिनिंग, प्रेसिंग, पावरलूम, तेल मिलों, चावल व दाल मिलों, काफी, चाय, रबड़, फल और सब्जी प्रसंस्करण इकाइयों समेत कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, आधुनिकीकरण विस्तार व विविधीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 1950 में जहां सहकारी क्षेत्र में केवल दो चीनी मिलें थी वह आज बढ़कर 312 तक पहुंच गई हैं। देश के कुल चीनी उत्पादन में सहकारी चीनी मिलों की हिस्सेदारी 36 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। सहकारी क्षेत्र में नई चीनी मिलों की स्थापना, पुरानी मिलों के आधुनिकीकरण और पेराई क्षमता के विस्तार के लिए सहायता दी जाती है। चीनी निर्यात में भी सहकारी चीनी मिलों की हिस्सेदारी 31 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है। फिलहाल सहकारिता मंत्रालय का पूरा जोर चीनी उत्पादन के साथ एथनॉल उत्पादन पर है। सहकारी चीनी मिलों को एथेनॉल संयंत्र, सह उत्पादन संयंत्र की स्थापना और कार्यशील पूंजी के लिए एनसीडीसी ने वित्त वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक 48 मिलों को 9,893.12 करोड़ रुपए के 87 लोन स्वीकृत किए हैं। 2024-25 में इन्हें 7,975.54 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है।

मार्केटिंग कांप्लेक्स और कस्टम हायरिंग केंद्र खोलने को मदद

सरकार लघु व सीमांत किसानों को कृषि

संबंधी मशीनरी और उपकरण उपलब्ध कराने के लिए राज्यों की प्राथमिक सहकारी समितियों को पर्याप्त वित्तीय मदद मुहैया कराती है। मार्केटिंग क्षेत्र में सक्रिय सहकारी समितियों को मार्केटिंग कांप्लेक्स की स्थापना करने और कस्टम हायरिंग केंद्र खोलने को सहायता दी जाती है। सहकारिता मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप एनसीडीसी से पैक्स व ब्लॉक व जिला स्तर की सहकारी समितियों को उनकी मांग के अनुरूप वित्तीय आवंटन किया जाता है।

सर्विस कोऑपरेटिव

कृषि मंत्रालय के कृषि उत्पादों की एमएसपी पर होने वाली खरीद और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र के साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए सेवा सहकारिता (सर्विस कोऑपरेटिव) क्षेत्र पर खूब जोर है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां से ग्रामीण युवाओं को नए उद्यम शुरू करने का भी मौका देता है। जल संरक्षण कार्य और सेवाएं, सिंचाई संसाधनों में सूक्ष्म सिंचाई के साथ पशुधन विकास और स्वास्थ्य सेवा और बीमारियों की रोकथाम जैसे कार्यों को सहकारिता क्षेत्र में खास तरजीह दी जाती है। इस क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करने वाली सहकारिताओं को विशेष तवज्जो दी गई है। सहकारिता के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्राथमिकता वाले क्षेत्र ग्रामीण स्वच्छता, जल निकासी और ग्रामीण सीवेज प्रणाली को सहायता प्रदान की जाती है।

टेक्सटाइल्स कोऑपरेटिव

टेक्सटाइल्स कोऑपरेटिव क्षेत्र में कमजोर वर्ग की मदद के लिए एनसीडीसी कताई मिलों, बुनाई, कढ़ाई और गारमेंटिंग की आवश्यकता के हिसाब से धन आवंटन करता है। सहकारी क्षेत्र की कताई मिलें इस समय 38 लाख तकुओं (स्पिंडल्स) और 10,670 रोटरों की स्थापित क्षमता के साथ चल रही हैं। इसके तहत विभिन्न राज्यों की मांग के अनुरूप वित्तीय मदद मुहैया कराई जाती है। बुनकरों की सहकारी समिति के साथ सहकारी पावरलूम इकाइयां भी संचालित हो रही हैं। ■

कुल वित्तीय प्रोत्साहन और प्रमुख लाभार्थी राज्य

वित्त वर्ष	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22
कुल ऋण (करोड़ रुपए में)	95,182.84	60,618.47	41,031.40	34,221.08
छत्तीसगढ	28,080	18,990	8,500	12,400
आंध्र प्रदेश	20,980.07	13,269.90	9,686.19	--
तेलंगाना	16,330	11,930.99	9,091.26	9,906.57
पंजाब	5,702	--	--	--
हरियाणा	--	--	--	12,824.83

डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास में बढ़ी भूमिका

सहकारिता मंत्रालय के फोकस एरिया में लघु व सीमांत किसानों के साथ भूमिहीन किसान भी हैं। इसीलिए पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र में काम करने वाली सहकारी समितियों को प्राथमिकता के आधार पर एनसीडीसी द्वारा वित्तीय मदद मुहैया कराई जाती है। डेयरी क्षेत्र की सहकारी समितियों को मजबूत कर ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए एनसीडीसी डेयरी सहकार नाम से एक योजना चलाती है। इस योजना का मकसद सहकारी समितियों के आधारभूत ढांचे का निर्माण, आधुनिकीकरण और विस्तार में मदद करना है। इसके लिए सहकारी समितियों को दीर्घकालिक ऋण, ऋण गारंटी और वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि डेयरी और पशुधन से जुड़ी सहकारी समितियों को एनसीडीसी ने वित्त वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक 1765.11 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद दी है। इसी तरह मत्स्य सहकारी समितियों को इस दौरान 818.24 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया गया है।

एनसीडीसी मत्स्य सहकारी समितियों को उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, विपणन आदि से संबंधित गतिविधियों को शुरू करने में सहायता प्रदान करता है। इन गतिविधियों में मछली पकड़ने वाली नावों, जालों और इंजनों जैसे परिचालन इनपुट की खरीद करने के अलावा विपणन, परिवहन वाहनों, बर्फ संयंत्रों, शीतगृहों, खुदरा दुकानों, प्रसंस्करण इकाइयों आदि के लिए बुनियादी ढांचा सुविधाओं का निर्माण करना शामिल है। साथ ही अंतर्देशीय मत्स्य पालन, जल संवर्धन, बीज फार्म, हैचरी आदि का विकास, व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने, एकीकृत मत्स्य पालन परियोजनाएं (समुद्री, अंतर्देशीय और खारे पानी) और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाज की खरीद के लिए भी आर्थिक मदद दी जाती है। मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए एनसीडीसी द्वारा कार्यान्वित योजनाओं में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) सबसे महत्वपूर्ण है जिसमें 40-60 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। इसी तरह मत्स्यपालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि के तहत सहकारी समितियों को 3 प्रतिशत तक ब्याज सहायता और प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना (पीएमएमकेएसएसवाई) के तहत 35 प्रतिशत तक कार्य निष्पादन सब्सिडी दी जाती है।

अहमदाबाद में डायल 112 के तहत जनरक्षक परियोजना का उद्घाटन कर बोले श्री शाह

सीमावर्ती व आंतरिक सुरक्षा को मजबूत कर आतंकवाद, नार्कोटिक्स और साइबर अपराध पर हुआ प्रभावी नियंत्रण

सहकार जागरण टीम

गुजरात ने न केवल सीमावर्ती सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया है, बल्कि आतंकवाद, नार्कोटिक्स, साइबर अपराध जैसे विभिन्न अपराधों पर भी प्रभावी रूप से अंकुश लगाया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने पुख्ता सीमावर्ती और आंतरिक सुरक्षा का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि सुशासन से प्रेरित नेतृत्व शासन की बागडोर संभाले तो बहुत कुछ परिवर्तन संभव है। श्री शाह अहमदाबाद में आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने गुजरात की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए '112 जनरक्षक' प्रोजेक्ट के रूप में राज्य गृह विभाग के उठाये इस कदम को ऐतिहासिक बताया, जिसका उद्घाटन उन्होंने किया। उन्होंने बताया कि यह प्रोजेक्ट देश की आंतरिक सुरक्षा, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी आपातस्थिति में हर प्रकार की सुविधा समय पर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शी पहल है।

- **आंतरिक सुरक्षा, नागरिक अधिकारों की रक्षा, कानून-व्यवस्था और त्वरित सुविधाओं के लिए दूरदर्शी पहल है डायल 112**
- **पीसीआर वैन का काफिला गुजरात में जनता की सेवा तैनात, तत्काल मिलेगी हर सुरक्षा सेवा**

श्री शाह ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर श्री मोदी ने जो मार्ग प्रशस्त किया था, उसे राज्य सरकार ने आगे बढ़ाया है और गुजरात को देश का सबसे सुरक्षित राज्य बनाने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है और राज्य की सीमाओं को दुश्मनों के लिए अभेद्य बनाने का कार्य किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि गुजरात देश के सबसे संवेदनशील सीमावर्ती राज्यों में से एक है। देश की उत्तरी सीमा से लेकर गुजरात तक का समूचा सीमावर्ती क्षेत्र कई मायनों में संवेदनशील है, जहां सुरक्षा का विशेष महत्व है।

प्रोजेक्ट जनरक्षक से उपलब्ध होगी त्वरित सुरक्षा

श्री शाह ने '112 जनरक्षक' प्रोजेक्ट के लोकार्पण के साथ गुजरात पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा 217 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित आवासों और कार्यालयों का उद्घाटन और कुल 1000 पुलिस वाहनों का लोकार्पण भी किया। उन्होंने खुशी जताई कि गुजरात 'डायल 112 जनरक्षक' के नक्शे में अपना स्थान दर्ज कर रहा है। श्री शाह ने कहा कि अब तक विभिन्न टोल-फ्री नंबरों का जाल, जैसे पुलिस के लिए 100, एम्बुलेंस के लिए 108, फायर सर्विस के लिए 101, महिला हेल्पलाइन के लिए 181, चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए 1098, आपदा के लिए 1070 और 1077 लोगों को भ्रमित कर रहा था, लेकिन अब देशवासियों को आपदा प्रबंधन, चाइल्ड हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन, फायर सर्विस, एम्बुलेंस और पुलिस सहायता जैसी किसी भी प्रकार की सुरक्षा संबंधी सेवा एक ही नंबर यानि 112 डायल करने से बहुत कम समय में उपलब्ध हो जाएगी। श्री शाह ने कहा कि एक अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर से संचालित कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी प्रकार की सेवाओं का समन्वय और जीपीएस से सुसज्जित वाहन एक वैज्ञानिक व्यवस्था के तहत कार्य करेंगे। ये वाहन, जिसमें 108 एम्बुलेंस का बड़ा काफिला शामिल है, कॉल करने वाले व्यक्ति के लोकेशन का पता लगाकर निकटतम पुलिस, एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड वाहन तक सूचना पहुंचाएंगे।

न्यू एज स्मार्ट पुलिसिंग सिस्टम की दिशा में बड़ा कदम

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देशभर की पुलिस के लिए जो स्मार्ट पुलिसिंग का आह्वान किया था, जिसका गुजरात सरकार ने आधुनिक तकनीक से सुसज्जित होकर शानदार निर्वहन किया है। यह न्यू एज स्मार्ट पुलिसिंग सिस्टम की दिशा में राज्य सरकार का यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके लिए सरकार प्रतिवर्ष 92 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यह परियोजना स्टेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर के माध्यम से संचालित होगी, जो अहमदाबाद में केंद्रीय प्रबंधन के तहत 24 घंटे कार्यरत रहेगा। 150 सीटों की क्षमता वाला यह कॉल सेंटर हर सेकंड सतर्क रहकर एकीकृत प्रणाली के माध्यम से सभी प्रकार की सेवाओं से जुड़ा रहेगा। डायल 112 जनरक्षक पीसीआर वैन का काफिला, जिसमें कुल 1000 वाहन शामिल हैं, तत्काल ही जनता की सेवा में तैनात हो जाएगा। इन वाहनों में लाइट बार, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, एमडीटी वायरलेस सेट, लोकेशन ट्रैकर जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके साथ ही प्रशिक्षित कर्मचारियों की व्यवस्था भी प्रभावी ढंग से की गई है।

माणसा पुलिस स्टेशन को बीआईएस प्रमाणन प्राप्त हुआ

श्री शाह ने कहा कि माणसा के पुलिस स्टेशन को बीआईएस प्रमाणन प्राप्त होना उनके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वे माणसा में ही जन्मे, बड़े हुए और वहीं से गुजरात एवं देश की राजनीति में योगदान देने के योग्य बने, इसलिए माणसा के पुलिस स्टेशन को बीआईएस प्रमाणन प्राप्त होना उनके लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है।

उन्होंने कहा कि पुलिस, होमगार्ड और जेल कर्मचारियों के कार्य और निवास के लिए गुजरात पुलिस हाउसिंग बोर्ड ने 217 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न परियोजनाओं का निर्माण किया है। इन इमारतों में उपलब्ध बेहतर सुविधाओं के साथ पुलिस कर्मचारी, होमगार्ड जवान और जेल कर्मचारी जनता की सेवा और भी प्रभावी ढंग से कर सकेंगे।

आतंकवाद के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति को वास्तविकता में लागू किया

श्री शाह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और गुजरात के गौरवशाली पुत्र श्री मोदी ने पिछले 11 वर्षों में 'आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस' की नीति को न केवल सिद्धांत, बल्कि वास्तविकता में लागू किया है। चाहे देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र हों, नक्सल प्रभावित क्षेत्र हों, या कश्मीर हो, इन तीनों हॉटस्पॉट में आतंकवादियों और हथियारबंद समूहों को सरकार ने सबक सिखाया है। पूर्वोत्तर में 10,000 से अधिक उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। ■

अहमदाबाद में सरदार धाम ट्रस्ट के फेज दो में छात्रा हॉस्टल का उद्घाटन

आत्मनिर्भर बेटियां राष्ट्र निर्माण में निभाएंगी महत्वपूर्ण भूमिका

सहकार जागरण टीम

देश भर में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं। देश में 'बेटी-बचाओ, बेटी पढ़ाओ' एक राष्ट्रव्यापी जन अभियान बन गया है और बेटियों को शिक्षित करने, उनका सम्मान बढ़ाने और उनके लिए भव्य छात्रावासों के निर्माण सहित अन्य सुविधाएं जुटाने के लिए लोग अब सक्रिय रूप से आगे आ रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इन विचारों को गुजरात के अहमदाबाद में सरदार धाम ट्रस्ट के एक शैक्षिक समारोह में वीडियो संदेश के माध्यम से व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य समाज में सकारात्मक योगदान देने वाले व्यक्तियों का पोषण करना और उनकी क्षमताओं को बढ़ाना है। छात्राओं के लिए 200 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हॉस्टल को बेटियों की सेवा और शिक्षा के लिए समर्पित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस छात्रावास में रहने वाली बेटियां जब आत्मनिर्भर और सक्षम हो जाएंगी, तब वे राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या के पाप की निंदा करते हुए इसे एक गंभीर कलंक बताया। श्री मोदी ने कहा कि गुजरात नारी शक्ति की पूजा करता है और चाहे वह उमिया माता हो, खोडियार माता हो, काली माता हो, अंबा माता हो या बहुचर माता हो, उसे कन्या भ्रूण हत्या का कलंक नहीं सहना चाहिए। गुजरात में पुरुष-महिला शिशु अनुपात का अंतर सफलतापूर्वक कम होना

- **देश भर में अवसंरचना विकास रिकॉर्ड गति से हो रहा है: प्रधानमंत्री**
- **सरदार धाम ट्रस्ट वडोदरा, सूरत, राजकोट और मेहसाणा में शुरू करेगा परियोजनाएं: श्री अमित शाह**
- **भारत के श्रम और प्रतिभा का दुनिया में बहुत सम्मान, इससे विभिन्न देशों में उभर रहे अनगिनत अवसर**
- **भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, समाज को दृढ़ विश्वास के साथ स्वदेशी उत्पादों को अपनाना चाहिए**

शुरू हो गया है।

इस अवसर पर श्री मोदी ने भारत की कुशल जनशक्ति की वैश्विक मांग का जिक्र किया और कहा कि दुनिया बढ़ती उम्र की आबादी की एक बड़ी चुनौती का सामना कर रही है। ऐसे में, दुनिया में युवा प्रतिभाओं की बहुत जरूरत है। उन्होंने पिछली सरकारों द्वारा दशकों से लागू पुरानी शिक्षा प्रणाली की आलोचना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौशल विकास पर सबसे अधिक जोर देती है। भारत सरकार विभिन्न क्षेत्रों में स्किल इंडिया मिशन के तहत लाखों युवाओं को कुशल जनशक्ति के रूप में तैयार कर रही है।

श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान में अस्थिर वैश्विक वातावरण में भारत के लिए आगे बढ़ने का सबसे अच्छा रास्ता आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भरता का अर्थ स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देना और 'मेक इन इंडिया' पहल के प्रति उत्साह बढ़ाना है। उन्होंने जोर देकर कहा, 'स्वदेशी आंदोलन कोई सदियों पुराना स्मृति चिन्ह नहीं है, बल्कि एक ऐसा अभियान है जो भविष्य को मजबूत करता है।' उन्होंने दोहराया कि 'देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास रिकॉर्ड गति से हो रहा है।' प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना के तहत बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना की जा रही है। भारत के ड्रोन और रक्षा उद्योगों में निरंतर वृद्धि हो रही है।

सरदार धाम ट्रस्ट ने बेटियों के आवास की उत्कृष्ट व्यवस्था की

इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को संबोधित किया और कहा कि सरदार धाम ट्रस्ट ने समाज की हजारों बहन-बेटियों को उनके शैक्षिक और व्यावसायिक मार्ग में मार्गदर्शन प्रदान करने के साथ-साथ उनके लिए आवास की उत्कृष्ट व्यवस्था करने का सराहनीय कार्य किया है। उनके संसदीय क्षेत्र में किया गया यह पुण्य कार्य हजारों बेटियों को शिक्षा प्राप्त करने और उनके करियर को उज्ज्वल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। श्री शाह ने कहा कि सरदार धाम ट्रस्ट वडोदरा, सूरत, राजकोट और मेहसाणा में अनेक परियोजनाएं शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 1960 में गुजरात की स्थापना के बाद से आज तक गुजरात और पाटीदार समाज का विकास समान रूप से हुआ है। पाटीदार समाज ने बालिका शिक्षा, व्यापार और उद्योग, कृषि सहित हर क्षेत्र में गुजरात और देश के विकास में बड़ा योगदान दिया है।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ग्रामीण, शहरी, आदिवासी और समुद्र तटीय क्षेत्र में समग्र विकास की नींव रखी है। मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी ने जो गुजरात मॉडल बनाया, उसने न केवल राज्य बल्कि भारत को वैश्विक मंच पर एक 'ग्लोबल गेटवे' के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।■

अर्थव्यवस्था की मजबूती से नागरिकों के जीवन में उत्थान

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि अर्थव्यवस्था की मजबूती से प्रत्येक नागरिक के जीवन में सुविधाएँ और समृद्धि आती है। गुजरात मॉडल ने न केवल राज्य को बल्कि भारत को वैश्विक मंच पर एक ग्लोबल गेटवे के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने छोटी-छोटी योजनाओं से लेकर वाइब्रेंट गुजरात जैसे विशाल आयोजनों तक को कार्यान्वित कर गुजरात को आज इस मुकाम तक पहुँचाने में अभूतपूर्व योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि गुजरात के युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आईपीएस, आईएएस, आईआरएस, और कस्टम सर्विस जैसी सेवाओं की सूची में गुजरातियों के नाम बहुत कम देखने को मिलते हैं। यदि एक सुनियोजित पद्धति से उनका प्रशिक्षण हो, तो उनकी संख्या में वृद्धि हो सकती है। इस हॉस्टल में पुस्तकालय, ई-पुस्तकालय, रीडिंग रूम जैसी सुविधाओं के साथ एक सम्पूर्ण परिसर विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सरदार धाम ट्रस्ट ने वडोदरा, मध्य गुजरात, दक्षिण गुजरात के सूरत, सौराष्ट्र के राजकोट, और उत्तर गुजरात के मेहसाणा में अनेक परियोजनाएं शुरू करेगा। श्री अमित शाह ने कहा कि सरदार धाम में अब तक लगभग 52,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य पूरा किया जा चुका है और अब लगभग 10,000 विद्यार्थियों को यूपीएससी, जीपीएससी, रक्षा सेवाओं, और न्यायिक सेवाओं की परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि गुजराती समाज के युवाओं के प्रशिक्षण के इस कार्यक्रम में भारत सरकार और गुजरात सरकार सरदार धाम को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। श्री अमित शाह ने कहा कि यह बहुत बड़ी बात है कि पाटीदार समाज के जिन लोगों ने सफलता प्राप्त की है, जिन पर लक्ष्मीजी की कृपा हुई है, वे सभी भामाशाह बन गए हैं और उन्होंने बाकी समाज को आगे बढ़ाने का अभियान चलाया है। राज्य भर में कई संस्थान स्थापित किए गए हैं और समाज कल्याण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। पूरे देश में अगर कोई बड़ा उदाहरण है कि जहां बेटी पढ़ती है, वह समाज सफलता प्राप्त कर सकता है और तेजी से विकास कर सकता है, तो वह पाटीदार समाज है। श्री शाह ने राज्य भर में विभिन्न इकाइयों के माध्यम से सरदार धाम के महान संकल्प को साकार करने के लिए कार्यरत सरदार धाम को केंद्र और राज्य सरकारों से पूर्ण सहयोग मिलने का आश्वासन दिया और अपनी शुभकामनाएं दीं।

गुवाहाटी में गोलाप बरबोरा के जन्मशती समारोह में बोले श्री अमित शाह

देश को घुसपैठिया मुक्त करने का संकल्प होगा पूरा

- देश की मतदाता सूची लोकतंत्र का हृदय, विदेशी नागरिकों को इसमें जगह नहीं
- हाई-पावर डेमोग्राफिक मिशन देश को घुसपैठिया मुक्त बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगा

सहकार जागरण टीम

किसी भी देश की मतदाता सूची लोकतंत्र का हृदय होती है। इसमें विदेशी नागरिकों को स्थान नहीं मिलना चाहिए। सामाजिक जीवन में नैतिक पतन इतना बढ़ गया है कि मतदाता सूची से घुसपैठियों को हटाने का विरोध किया जा रहा है। यदि आज गोलाप बरबोरा जी होते, तो वे निश्चित रूप से इसका विरोध करते। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने असम के पूर्व मुख्यमंत्री श्री गोलाप बरबोरा के जन्मशती समारोह के दौरान गुवाहाटी में इन विचारों को व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि असम और पूरे देश को घुसपैठिया मुक्त करने का हमारा संकल्प है, जिसे हम अवश्य पूरा करेंगे। हम दृढ़ता से यह मानते हैं कि इस देश में एक भी घुसपैठिया नहीं रहना चाहिए और इसके लिए गोलाप बरबोरा जी के जन्मशती वर्ष से बेहतर समय कोई और नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को बरबोरा जी के सिद्धांतों के आधार पर एक हाई-पावर डेमोग्राफिक चेंजेस मिशन के गठन की घोषणा की। यह मिशन देशभर में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करेगा, घुसपैठियों की पहचान करेगा और देश को घुसपैठियों से मुक्त कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

श्री शाह ने कहा कि असम में सबसे पहले घुसपैठ के खिलाफ गोलाप बरबोरा जी ने मतदाता सूची के शुद्धिकरण के माध्यम से जागरूकता फैलाई। मुख्यमंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल में मतदाता सूचियों की जांच

की गई। उस समय संसाधनों की कमी और मतदाता सूचियों के कंप्यूटरीकरण न होने के बावजूद गोलाप बरबोरा जी ने 36,780 अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची से हटाने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि यदि कोई असम आंदोलन की नींव खोजेगा, तो वह इस मतदाता सूची शुद्धिकरण से ही निकलेगी।

घुसपैठियों के खिलाफ की गई सराहनीय कार्रवाई

श्री शाह ने कहा कि असम सरकार द्वारा घुसपैठियों के खिलाफ की गई कार्रवाई सराहनीय है। सरकार ने घुसपैठियों द्वारा कब्जाई गई एक लाख 26 हजार एकड़ भूमि को मुक्त कराया है। राज्य के शोणितपुर में 49,500 बीघा, दरंग में 17,095 बीघा, लखीमपुर में 13,438 बीघा, होजाई में 10,749 बीघा और ग्वालपाड़ा में 8,280 बीघा जमीन अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई। उन्होंने कहा कि न केवल काजीरंगा के जंगल और वन क्षेत्र को घुसपैठियों से मुक्त कराया गया, बल्कि शंकरदेव और माधवदेव के सत्रों की हजारों एकड़ भूमि को भी मुक्त कराकर इन महापुरुषों के सम्मान और सत्रों की पवित्रता को पुनः स्थापित करने का कार्य हुआ। श्री शाह ने कहा कि आज चुनाव आयोग मतदाता सूची का शुद्धिकरण कर रहा है और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की दिशा में कार्य कर रहा है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल घुसपैठियों के बचाव में यात्राएं निकाल रहे हैं।

श्री शाह ने कहा कि असम सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान का नाम गोलाप बरबोरा जी के नाम पर रखा है। पूरे वर्ष हर तहसील और हर जिले में गोलाप बरबोरा जी के जीवन, कार्यों और विचारों का प्रचार-प्रसार करने से निश्चित रूप से असम का भविष्य उज्ज्वल होगा। उन्होंने कहा कि असम सरकार ने बच्चियों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ी योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत लगभग 9,72,940 छात्राओं को अनुदान दिया गया। योजना के तहत ग्रेजुएट छात्राओं को एक हजार रुपए प्रति माह, डबल ग्रेजुएट को 1250 रुपए प्रति माह और स्नातकोत्तर स्तर पर 2500 रुपए प्रति माह सहायता दी जा रही है।

बरबोरा जी जीवन भर शोषित और वंचित वर्ग की आवाज रहे

श्री शाह ने कहा कि 1978 में जब गोलाप बरबोरा असम के मुख्यमंत्री बने, तो यह असम के राजनीतिक इतिहास में एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत थी। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन और आजादी मिलने के बाद लोकतंत्र को बचाने के आंदोलन और समाजवादी विचारधारा की सभी अच्छाइयों को असम राज्य में धरातल पर उतारा। मात्र 17 महीनों के छोटे से कार्यकाल में मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी। भारत रत्न से सम्मानित असम के प्रख्यात गायक रहे भूपेन हजारिका की उक्ति 'मनुष्य मनुष्य के लिए है और जीवन जीवन के लिए है', का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि गोलाप बरबोरा ने इस उक्ति को चरितार्थ किया और जीवन भर शोषित और वंचित वर्ग की आवाज बने रहे। उन्होंने संविधान की मर्यादा की रक्षा की, सत्तावाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ अलख जगाई और असम की विशिष्ट पहचान के साथ-साथ राज्य में बसी देश की आत्मा को जागरूक करने का काम किया।

श्री शाह ने कहा कि गोलाप बरबोरा जी ने सार्वजनिक जीवन में अपने-पराए और दलीय राजनीति से ऊपर उठकर अच्छा कार्य किया। उनमें देशभक्ति, समाजवाद और गरीबों के प्रति संवेदनशीलता जैसे गुण यूं ही नहीं आए थे। इसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समाजवादी सिद्धांतों पर चलते हुए असम और देश के मजदूरों, गरीबों और पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित किया और स्पष्ट रूप से कहा कि पूर्वोत्तर भारत देश से बाहर नहीं, बल्कि भारत के हृदय का अटूट हिस्सा है। श्री शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में बरबोरा जी ने अल्प कार्यकाल में ऐसे निर्णय किए, जो वर्षों तक असम की जनता को याद रहेंगे। उन्होंने असम में 10वीं कक्षा तक की पूरी पढ़ाई मुफ्त कर दी और एक वर्ष में 200 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की। जिन किसानों की 10 बीघा तक की जमीन थी, उन सभी किसानों का लगान बरबोरा जी ने हमेशा के लिए माफ कर दिया। उन्होंने छोटे चाय बागानों की नीति लाकर चाय बागान की खेती भी किसानों के लिए खोली। पहली बार असम में बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड और रेलवे भर्ती बोर्ड की स्थापना करकर असम में उस समय कौशल प्रदान करने का प्रयोग बरबोरा जी किया। श्री शाह ने कहा कि राज्य व देश के युवाओं के लिए उनके योगदान की जानकारी उपलब्ध कराने का नेक कार्य असम सरकार ने किया है। ■

बिहार में 12,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण कर बोले प्रधानमंत्री श्री मोदी

बिहार के बेटे बेटियों को राज्य के भीतर ही मिलेगा रोजगार

सहकार जागरण टीम

बिहार के बेटे-बेटियों को राज्य के भीतर ही रोजगार उपलब्ध कराने का भरोसा देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि पूरे बिहार में बड़ी-बड़ी परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र गया जी ज़िले के डोभी में स्थापित किया जा रहा है। गया जी में एक प्रौद्योगिकी केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। बक्सर थर्मल पावर प्लांट और औरंगाबाद में नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भागलपुर के पीरपैंती में एक नया थर्मल पावर प्लांट बनाया जाएगा। ये विद्युत संयंत्र बिहार में बिजली की आपूर्ति बढ़ाएंगे। विद्युत उत्पादन बढ़ने से घरों में बिजली की उपलब्धता में सुधार होने और उद्योगों के लिए अधिक आपूर्ति होने की बात कहते हुए श्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा के बुनियादी ढांचे में यह विस्तार नए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी बिहार के गया जी में 12 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे।

- राज्य में बड़ी परियोजनाएं हो रही स्थापित, सृजित होंगे रोजगार
- अकेले बिहार में बनाए गए 38 लाख गरीबों के पक्के मकान
- ऑपरेशन सिंदूर भारत की रक्षा रणनीति में एक नई लकीर

बिहार को चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की भूमि बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि जब भी भारत को अपने दुश्मनों से चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, बिहार राष्ट्र के लिए एक ढाल बनकर खड़ा रहा है। बिहार की धरती पर लिया गया कोई भी संकल्प कभी अधूरा नहीं रहता।

कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का उल्लेख करते हुए, जहां धर्म पूछकर निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी गई थी, प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि बिहार की धरती से उन्होंने आतंकवाद को खत्म करने की कसम खाई थी। आज दुनिया बिहार की धरती पर लिए गए उस संकल्प को पूरा होते हुए देख रही है। जब पाकिस्तान ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहा था, तब भारत तिनके की तरह उन मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर रहा था। पाकिस्तान की एक भी मिसाइल भारत को नुकसान नहीं पहुंचा पाई। ऑपरेशन सिंदूर को भारत की रक्षा रणनीति में एक नई लकीर बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि अब भारत में आतंकवादी भेजने या हमलों को अंजाम देने के बाद कोई भी नहीं बच सकता है। अगर आतंकवादी पाताल में भी छिप जाएं, तब भी भारत की मिसाइलें उन्हें वहीं दफन कर देंगी।

औंटा-सिमरिया ब्रिज की आधारशिला रखने और इसका अब खुद उद्घाटन करने की बात कहते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ब्रिज उत्तर और दक्षिण बिहार को भी जोड़ेगा। पहले गांधी सेतु के रास्ते 150 किलोमीटर का चक्कर लगाने वाले भारी वाहनों के पास अब एक सीधा मार्ग होगा। यह व्यापार को गति देगा, उद्योगों को मजबूत करेगा और तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा को आसान बनाएगा।

राज्य में रेलवे के विकास का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत गया जी रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को हवाई अड्डे जैसी सुविधाएं प्रदान की जा सकें। गया अब राजधानी, जन शताब्दी और मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेनों तक पहुंच वाला शहर है। गया जी से सासाराम, प्रयागराज और कानपुर के माध्यम से दिल्ली तक सीधी रेल कनेक्टिविटी बिहार के युवाओं और उद्यमियों के लिए नए अवसर पैदा कर रही है। ■

असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र विंग का उद्घाटन कर बोले श्री अमित शाह

मोदी सरकार में पूर्वोत्तर राज्यों का हुआ अभूतपूर्व विकास

- **सीमाओं की सुरक्षा, नारकोटिक्स व अवैध तस्करी को रोकने में जुटेंगे आठों राज्यों के पुलिसकर्मी**
- **पूर्वोत्तर में श्री शाह ने आठ परियोजनाओं का किया ई-शिलान्यास और लोकार्पण**

सहकार जागरण टीम

पूर्वोत्तर हमेशा से भारत की सुरक्षा का एक अहम स्तंभ रहा है। अनेक प्रकार के उतार-चढ़ावों और हिंसक संघर्षों को झेलते-झेलते आज पूर्वोत्तर शांति और संपूर्ण विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इन विचारों को असम के गुवाहाटी में व्यक्त किया। श्री शाह ने कहा कि विश्व में सबसे पुरातन और सबसे अधिक विविधताओं का समावेश करने वाली संस्कृति पूर्वोत्तर में मिलती है। यहां की कला, भाषाएं, खानपान, वेशभूषा, संगीत और प्राकृतिक सौंदर्य पूरे पूर्वोत्तर को विश्व में अद्भुत बनाते हैं। असम के इतिहास में महाराजा पृथु से लेकर लचित बोरफुकन और चिलाराय से लेकर सेना में भर्ती हुए यहां के युवाओं का मां भारती के लिए बलिदानों की लंबी ऋंखला है। असम बचाओ आंदोलन के संघर्ष के दौर में भी अनेक युवाओं ने बलिदान दिया। श्री शाह ने कहा कि उस समय विद्यार्थियों ने जिस कामना के साथ आंदोलन किया था, उसे चरितार्थ करने का कार्य प्रधानमंत्री श्री मोदी और मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा सरमा ने किया है। असम आंदोलन के समय जिस असम की कल्पना की गई थी, राज्य अब उससे भी आगे पहुंच चुका है और विकास की यह गति निरंतर जारी रहेगी। श्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में पूर्वोत्तर का अभूतपूर्व विकास हुआ है। श्री शाह ने कहा कि जब भी पूर्वोत्तर का इतिहास लिखा जाएगा, प्रधानमंत्री श्री मोदी के सेवाकाल के इन वर्षों को स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा।

श्री शाह ने 322 करोड़ रुपए से अधिक लागत की आठ परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीमाओं की सुरक्षा करने वाले केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों के लिए कई सुविधाओं की शुरुआत कर श्री शाह ने कहा कि लचित बोरफुकन पुलिस अकादमी में स्थापित एनसीएफएल के माध्यम से पूर्वोत्तर के आठों राज्यों के पुलिसकर्मी 24 घंटे देश की सीमाओं की सुरक्षा, नारकोटिक्स और अवैध तस्करी के खिलाफ लड़ाई में मदद करेंगे और नागरिकों की कमाई को सुरक्षित करेंगे। उन्होंने कहा कि लगभग 40 करोड़ रुपए से अधिक लागत और 3300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में बने राजनिवास के ब्रह्मपुत्र विंग में कई संवैधानिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने की सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

श्री शाह ने कहा कि श्री मोदी ने हर क्षेत्र में विकास की न सिर्फ नीतियां बनाईं, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारने का भी कार्य किया है, जिससे देशभर में हर क्षेत्र में प्रगति हुई है और दुनिया इसे अचंभित होकर देख रही है। श्री मोदी के नेतृत्व में डिजिटल भारत का स्वप्न साकार हो रहा है। साइबर सुरक्षा नागरिकों के लिए बेहद जरूरी है, इसीलिए सरकार ने वर्ष 2019 में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) के तहत दिल्ली में पहली नेशनल साइबर फॉरेंसिक लैबोरेट्री (एनसीएफएल) की स्थापना की, जो नागरिकों को उनकी मेहनत की कमाई को साइबर अपराधियों से बचाने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के बाद असम के गुवाहाटी में दूसरी एनसीएफएल बनी है, जो पूर्वोत्तर के सभी आठ राज्यों के नागरिकों की कमाई को सुरक्षित करेगी। देश की सुरक्षा में भी एनसीएफएल मददगार साबित होगी और डार्क नेट का उपयोग कर नारकोटिक्स, हथियारों की तस्करी और भारत की सीमाओं में गैप ढूंढकर घुसपैठ का प्रयास करने वालों के खिलाफ उपयोगी साबित होगा। ■

इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में बोले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

विकसित भारत की आधारशिला है आत्मनिर्भर भारत

सहकार जागरण टीम

भारत वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए प्रतिबद्ध है। आत्मनिर्भर भारत ही विकसित भारत की आधारशिला है। यह विचार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मूल्यांकन तीन प्रमुख मानदंडों गति, पैमाना और दायरा पर किया जा सकता है। कोविड के दौरान भारत ने इन तीनों मानकों का प्रदर्शन किया। उस दौरान आवश्यक वस्तुओं की मांग में अचानक वृद्धि हुई। जबकि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं ठप हो गईं थीं। भारत ने आवश्यक वस्तुओं के घरेलू स्तर पर निर्माण के लिए निर्णायक कदम उठाए। बड़ी मात्रा में परीक्षण किट और वेंटिलेटर का तेजी से उत्पादन किया और देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए।

देश के कोने-कोने में नागरिकों को 220 करोड़ से ज्यादा भारत-निर्मित टीके मुफ़्त में लगाए गए। लाखों लोगों का तेजी से टीकाकरण करने के लिए को-विन प्लेटफॉर्म विकसित किया। भारत ने अपनी कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न करने का लक्ष्य तय समय से पांच साल पहले वर्ष 2025 में ही हासिल कर लिया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि एक आत्मनिर्भर भारत निर्यात में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। पिछले वर्ष, भारत ने चार लाख करोड़ रुपए मूल्य के कृषि उत्पादों का निर्यात किया।

- **भारत दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर**
- **भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अनुसंधान को दिया जा रहा बढ़ावा**
- **भारत आज दुनिया को विकास की धीमी वृद्धि से उबारने की स्थिति में**

पिछले वर्ष दुनिया में उत्पादित 800 करोड़ वैक्सीन खुराकों में से 400 करोड़ भारत में निर्मित की गईं। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात का आंकड़ा लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए हो गया है। आज भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात एक वर्ष में 1.2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। भारत अब मेट्रो कोच, रेल कोच और रेल इंजनों का निर्यात शुरू कर चुका है। 100 देशों को इलेक्ट्रिक वाहन निर्यात करके एक और उपलब्धि हासिल करने के लिए तैयार है।

अनुसंधान को राष्ट्र की प्रगति का एक प्रमुख स्तंभ बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि आयातित अनुसंधान भारत की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता। अनुसंधान के क्षेत्र में तत्परता और एक केंद्रित मानसिकता की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार ने अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए तेजी से काम किया है और आवश्यक नीतियों और प्लेटफॉर्म्स का निरंतर विकास किया है। 11 वर्षों में अनुसंधान और विकास पर खर्च दोगुने से भी अधिक हो गया है। पेटेंट की संख्या 2014 से 17 गुना बढ़ गई है।

लगभग छह हजार उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान और विकास प्रकोष्ठ स्थापित किए जाने की जानकारी देते हुए श्री मोदी ने कहा कि 'एक राष्ट्र, एक सदस्यता' पहल ने छात्रों के लिए वैश्विक शोध पत्रिकाओं को और अधिक सुलभ बना दिया है। 50 हजार करोड़ रुपए के बजट से एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन बनाया गया है और एक लाख करोड़ रुपए मूल्य की एक अनुसंधान विकास और नवाचार योजना को भी मंजूरी दी गई है।

श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान समय उद्योग और निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी की मांग करता है। उन्होंने विशेष रूप से स्वच्छ ऊर्जा, क्वांटम प्रौद्योगिकी, बैटरी भंडारण, उन्नत सामग्री और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान और निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।

भारत को अब दुनिया को धीमी विकास दर की गिरफ़्त से बाहर निकालने में मदद करने की स्थिति में होने की बात कहते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत ठहरे हुए पानी में कंकड़ फेंकने वाला देश नहीं है, बल्कि वह देश है जिसके पास तेज बहाव वाली धाराओं को मोड़ने की क्षमता है। यह अब समय की धारा को भी नया रूप देने की क्षमता रखता है।

भारत को वर्तमान में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जल्द ही भारत विश्व स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। भारतीय कंपनियां पूंजी बाजारों से रिकॉर्ड धन जुटा रही हैं, भारतीय बैंक पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं, मुद्रास्फीति बहुत कम है तथा ब्याज दरें भी कम हैं। भारत का चालू खाता घाटा नियंत्रण में है और विदेशी मुद्रा भंडार अच्छी स्थिति में है। हर महीने लाखों घरेलू निवेशक बाजार में हजारों करोड़ रुपए का निवेश कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले 11 साल में भारत की सौर पीवी मॉड्यूल निर्माण क्षमता लगभग 2.5 गीगावाट से बढ़कर 100 गीगावाट तक पहुँच गई है, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

अपनी सुदृढ़ता और ताकत के माध्यम से भारत को वैश्विक विश्वास का स्रोत बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपना पूरा 5जी तकनीक को घरेलू स्तर पर विकसित किया है। भारत ने न केवल मेड-इन-इंडिया 5जी का निर्माण किया, बल्कि इसे सबसे तेज गति से पूरे देश में तैनात भी किया। भारत अब मेड-इन-इंडिया 6जी तकनीक पर तेजी से काम कर रहा है। सेमीकंडक्टर से संबंधित कारखाने भारत में स्थापित हो रहे हैं। इस साल के अंत तक पहली मेड-इन-इंडिया चिप बाजार में उपलब्ध होगी।

भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास पर चर्चा करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में, जब हर बड़ा देश अंतरिक्ष में अवसरों की खोज कर रहा है, भारत पीछे नहीं रह सकता। अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार किए गए और इसे निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोल दिया गया। भारत ने इस वर्ष अंतरिक्ष डॉकिंग क्षमता हासिल कर ली है। गगनयान मिशन के तहत देश अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का अनुभव इस प्रयास में बहुत मददगार साबित होगा। स्पेक्ट्रम आवंटन पहली बार पारदर्शी बनाया गया है और अंतरिक्ष क्षेत्र में विदेशी निवेश को पहली बार उदार बनाया गया है। भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र अब सुधारों की सफलता देख रहा है। आज 300 से अधिक स्टार्टअप इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं।

जन विश्वास 2.0 पहल को विश्वास-आधारित और जन-हितैषी शासन से जुड़ा एक बड़ा सुधार बताते हुए कहा कि जन विश्वास के पहले संस्करण के तहत लगभग 200 छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। दूसरे संस्करण में अब 300 से ज्यादा छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। आयकर कानून को भी काफी सरल बना दिया गया है।

प्रधानमंत्री ने अनावश्यक कानूनों को निरस्त करने, नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे प्रमुख कदमों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रक्रियाओं और स्वीकृतियों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है, जबकि कई प्रावधानों को अपराध-मुक्त किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा, जीएसटी व्यवस्था में एक बड़ा सुधार किया जा रहा है और यह प्रक्रिया दिवाली तक पूरी हो जाएगी। इससे जीएसटी प्रणाली सरल हो जाएगी और कीमतें कम हो जाएंगी। ■

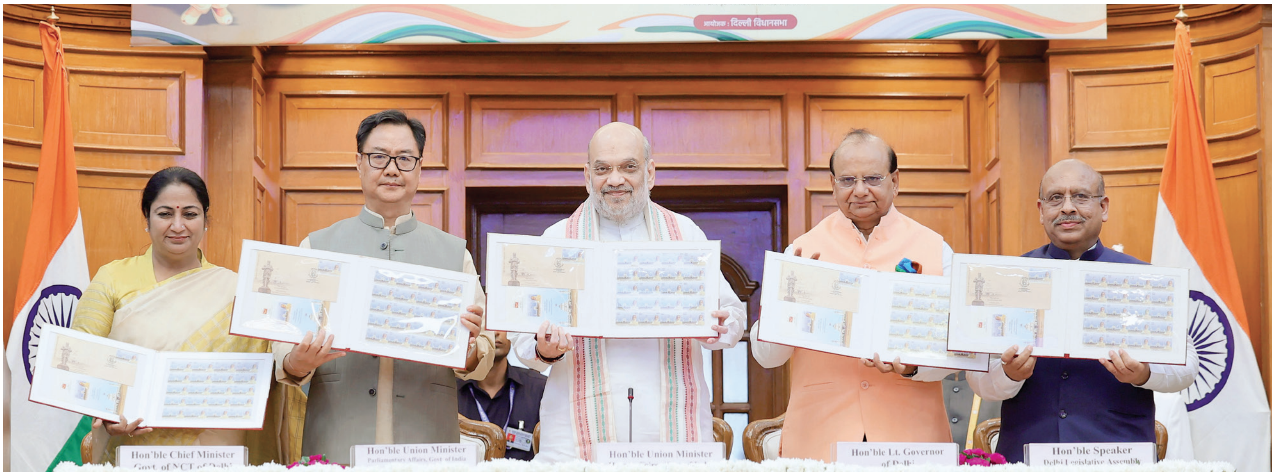

स्वतंत्रता सेनानी विट्ठलभाई पटेल के पहले निर्वाचित स्पीकर बनने के सौ वर्ष पर आयोजित समारोह में बोले श्री अमित शाह

राष्ट्रहित के विचार से ही लोकतंत्र को मिलेगी सर्वोच्च गरिमामयी ऊंचाई

सहकार जागरण टीम

- **विट्ठलभाई पटेल जी ने भारतीय विचारों के आधार पर लोकतांत्रिक ढंग से देश चलाने की रखी नींव**
- **विधायी कार्य व सभापति के दायित्वों के लिए मार्गदर्शन का काम कर रही उनकी स्थापित परंपराएं**

भारतीय विचारों के आधार पर लोकतांत्रिक ढंग से देश को चलाने की नींव डालने का कार्य यदि किसी ने किया तो निस्संदेह वे महान स्वतंत्रता सेनानी विट्ठलभाई पटेल जी ही थे। उन्होंने भारत की विधायी परंपराओं की नींव रखकर लोकतंत्र को मजबूत किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इन विचारों को दिल्ली विधानसभा में स्वतंत्रता सेनानी विट्ठलभाई पटेल के केंद्रीय विधानसभा के पहले निर्वाचित भारतीय स्पीकर बनने के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित अखिल भारतीय विधानसभा अध्यक्ष सम्मेलन के दौरान व्यक्त किया। श्री शाह ने कहा कि विट्ठलभाई को केंद्रीय विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने से भारतीयों द्वारा हमारे विधायी इतिहास की शुरुआत हुई। यह हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है कि हम अपनी-अपनी विधानसभाओं में सभापति के पद की गरिमा को बढ़ाने के लिए कार्य करें।

श्री शाह ने कहा कि महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय और देशबंधु चितरंजन दास जैसे अनेक महान विभूतियों ने इसी सदन से देशवासियों की स्वतंत्रता की उत्कंठा और आजादी के प्रति उनकी आकांक्षा को अपने प्रभावशाली संबोधनों के माध्यम से व्यक्त किया। महामना मदन मोहन मालवीय करीब 20 वर्षों तक इस सदन के सदस्य रहे। उन्होंने दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष को प्रेरित किया कि वे सदन में उन सभी महानुभावों के भाषणों का संकलन देश की सभी विधानसभाओं के पुस्तकालयों में उपलब्ध कराएं, जिससे देश के युवाओं व विधायकों को यह जानने को मिलेगा कि यहां किस प्रकार स्वतंत्रता की भावना जगाने का कार्य हुआ ? दिल्ली विधानसभा ने विट्ठलभाई पटेल के जीवन पर आधारित जो सुंदर प्रदर्शनी आयोजित की है, उसी प्रकार की प्रदर्शनी सभी विधानसभाओं में लगाई जाए, ताकि न केवल विट्ठलभाई के जीवन और उनके कार्यों, बल्कि स्वतंत्रता के इतिहास के बारे में भी देश के सभी विधायकों,

विधान परिषद के सदस्यों और युवाओं को जानकारी प्राप्त हो सके।

राष्ट्रहित के विचार से ही मजबूत होगा लोकतंत्र

श्री शाह ने कहा कि विधानसभाओं में किसान की हरी-भरी फसलों से लेकर युवाओं के स्वप्नों तक, महिला सशक्तीकरण से लेकर समाज के प्रत्येक पिछड़े वर्ग के कल्याण तक, देश की एकता और अखंडता से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक के हर विषय पर व्यापक चर्चाएं होती हैं। विधानसभा की कार्यवाही में विधान बनाना विधानसभा का मुख्य कार्य है और किसी भी कानून का अंतिम उद्देश्य जनकल्याण होना चाहिए। इसका अंतिम ध्येय सर्वस्पर्शी व सर्वसमावेशी विकास का मॉडल होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि जब विवेक, विचार और विधान का सभापति द्वारा पूर्ण सम्मान किया जाता है, तो विधानसभाएं दलगत हितों से ऊपर उठकर प्रदेश और देश के हितों पर विचार करती हैं और लोकसभा देश के हितों पर विचार करती है। दलगत हितों से ऊपर उठकर राष्ट्रहित का विचार ही हमें लोकतंत्र की सर्वोच्च गरिमामयी ऊंचाई तक पहुंचाने का एकमात्र मार्ग है।

विचार मंथन ही जन समस्याओं के निवारण का सर्वश्रेठ माध्यम

श्री शाह ने कहा कि आज हर विधानसभा अध्यक्ष का कर्त्तव्य है कि वे निष्पक्ष, सकारात्मक और रचनात्मक बहस को बढ़ावा दें ताकि देश के प्रत्येक वर्ग के हितों की रक्षा हो सके। हम अपने-अपने राज्यों की जनता की आवाज के लिए एक निष्पक्ष मंच स्थापित करें, पक्ष और विपक्ष द्वारा निष्पक्ष बहस सुनिश्चित करें और सदन की कार्यवाही विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के नियमों के अनुसार सुनिश्चित करें। विचार-मंथन ही लोकतंत्र में जनता की समस्याओं के समाधान का सर्वोत्तम माध्यम है। श्री शाह ने सावधान किया कि जब-जब सभाओं ने अपनी गरिमा खोई है, तब-तब हमें बहुत बुरे परिणाम भुगतने पड़े हैं। उन्होंने कहा कि सदन में सबसे कठिन भूमिका यदि किसी की होती है तो वह सभापति की होती है, क्योंकि वे किसी न किसी दल से चुनकर आते हैं, लेकिन सभापति की शपथ लेते ही एक निष्पक्ष अंपायर की भूमिका में आ जाते हैं। सभापति को एक संस्था का दर्जा दिया गया है। संविधान के 75 वर्षों में देश भर की विधानसभाओं और लोकसभा में सभापतियों ने हमेशा सदन की गरिमा को बढ़ाने का कार्य किया है। निष्पक्षता और न्याय ही दो ऐसे स्तंभ हैं जिन पर अध्यक्ष की गरिमा टिकी हुई है। एक प्रकार से अध्यक्ष को सदन का अभिभावक और सेवक दोनों माना जाता है। श्री शाह ने कहा कि हमने लगभग 80 वर्षों में लोकतंत्र की नींव को पाताल तक गहरा करके यह सिद्ध किया है कि भारतीय जनता के रग-रग और स्वभाव में लोकतंत्र बसा हुआ है।

लोकतंत्र का इंजन होता है सदन

सदन की गरिमा की याद दिलाते हुए श्री शाह ने जनप्रतिनिधियों से कहा कि वे देशहित में जनता की आवाज को अभिव्यक्ति देने का माध्यम बनें। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि प्रत्येक विधान यानी कानून जनमानस के विश्वास से ही उत्पन्न हो और उसी दिशा में आगे बढ़े। सदन लोकतंत्र का इंजन होता है और जब यहां स्वस्थ परंपराएं बनती हैं, देश की नीतियां निर्मित होती हैं और देशहित में कानून गढ़े जाते हैं तो राष्ट्र की दिशा स्वतः स्पष्ट हो जाती है। यदि संसद और विधानसभाओं के गलियारों में सार्थक वाद-विवाद नहीं होगा, तो वे केवल निर्जीव भवन बनकर रह जाएंगे। इन भवनों में भावनाओं और विचारों का निरूपण करने का कार्य सभापति के नेतृत्व में सदन के सभी सदस्यों का है, क्योंकि तभी यह एक जीवंत इकाई बनती है, जो देशहित और प्रदेशहित में कार्य करती है। श्री शाह ने कहा कि अपने राजनीतिक हितों के लिए संसद और विधानसभाओं को चलने न देना, यह वाद-विवाद नहीं है। विरोध संयमित होना चाहिए। प्रतीकात्मक विरोध का अपना स्थान है, लेकिन विरोध के बहाने दिन-प्रतिदिन और पूरे सत्र तक सदन को चलने न देने की जो परंपरा बन रही है, उस पर देश की जनता और चुने हुए प्रतिनिधियों को विचार करना होगा। ■

बिहार जीविका निधि साख सहकारी संघ का शुभारंभ

माताओं की गरिमा, गौरव व सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता : पीएम मोदी

- सशक्त महिलाएं विकसित भारत का आधार
- महिलाओं के जीवन में कठिनाइयां दूर करने को सरकार प्रतिबद्ध

सहकार जागरण टीम

माताओं की गरिमा, सम्मान और गौरव हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मां हमारे संसार का सार और स्वाभिमान का प्रतीक है। यह विचार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड के शुभारंभ के अवसर पर व्यक्त किया। बिहार में माताओं और बहनों को जीविका निधि साख सहकारी संघ के माध्यम से एक नई सुविधा प्रदान करने की बात कहते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस पहल से गांवों में जीविका से जुड़ी महिलाओं को सुगमता से वित्तीय सहायता मिलेगी, जो उनके काम और व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सहायक होगी।

सशक्त महिला को विकसित भारत का प्रमुख आधार बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए उनके जीवन की कठिनाइयां कम करना आवश्यक है। सरकार माताओं, बहनों और बेटियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए कई पहल कर रही है। खुले में शौच से मुक्ति के लिए महिलाओं के लिए करोड़ों शौचालयों का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों पक्के घर बनाए गए हैं, जिसका मालिकाना हक महिलाओं को देने पर ध्यान दिया गया है।

स्वच्छ पेयजल की समस्या के समाधान के लिए सरकार की 'हर घर जल' पहल का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि माताओं और बहनों को स्वास्थ्य सेवा की कठिनाइयां दूर करने के लिए आयुष्मान भारत योजना आरंभ की गई है। इसके तहत पांच लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार उपलब्ध कराया जाता है। सरकार की निःशुल्क राशन योजना भी चल रही है, जिससे हर मां अपने बच्चों का पेट भरने की चिंता से मुक्त हो गई है। महिलाओं की आय में बढ़ोतरी के लिए लखपति दीदी, ड्रोन दीदी और बैंक सखी जैसी पहल का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से महिलाएं सशक्त हो रही हैं।

बिहार में मातृशक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान सदैव सर्वोपरि होने की बात कहते हुए श्री मोदी ने कहा कि यहां गंगा मैया, कोसी मैया, गंडकी मैया और पुनपुन मैया जैसी देवी-देवताओं की श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है। मां जानकी बिहार की पुत्री थीं। छठी मैया की पूजा सबके लिए वरदान माना जाता है। नवरात्रि का पावन पर्व निकट आ रहा है, जिसमें मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा होती है। बिहार तथा पूर्वांचल क्षेत्र में सतबहिनी पूजा की भी परंपरा है, जिसमें सात बहनों को दिव्य मां के रूप में पूजा जाता है। मां के प्रति गहरी आस्था और भक्ति बिहार की एक विशिष्ट पहचान है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वह समाज और राष्ट्र की लगभग 55 वर्षों से सेवा कर रहे हैं। इस यात्रा में अपनी मां की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि हर मां अपने बच्चों के पालन-पोषण में अपार त्याग करती है और उसके लिए बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता। एक गरीब मां भी जीवन भर त्याग कर अपने बच्चों को शिक्षा और अच्छे संस्कार देती है। इसीलिए मां का स्थान देवताओं से भी ऊपर माना गया है।

जम्मू पहुंचकर श्री अमित शाह ने प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसानों का लिया जायजा

जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है मोदी सरकार

सहकार जागरण टीम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है और जनता की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करते हुए पुनर्वास और पुनर्निर्माण को सुगम बनाने के लिए त्वरित राहत, वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इन विचारों को प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जम्मू-कश्मीर पहुंचकर वहां के लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा। जम्मू संभाग के वर्षा, बाढ़ एवं भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर श्री शाह ने प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया और चक मांगू गांव के बाढ़-प्रभावित लोगों से भी मिले। तवी पुल, शिव मंदिर और जम्मू में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए घरों का निरीक्षण कर श्री शाह ने जन-हानि पर दुख व्यक्त किया और कहा कि संकट की इस घड़ी में पहले दिन से ही श्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने बचाव कार्यों में अपनी पूरी शक्ति लगा दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश और सभी एजेंसियों ने मिलकर संभावित नुकसान को बहुत कम किया है और समन्वित प्रयासों के साथ हम कई जानें बचाने में सफल हुए हैं। चूंकि जम्मू-कश्मीर प्राकृतिक आपदा-संभावित क्षेत्र है, इसीलिए केंद्र के हिस्से के रूप में राज्य आपदा मोचन निधि के लिए 209 करोड़ रुपए की राशि केंद्र शासित प्रदेश को आवंटित की गई है, जिससे यहां राहत कार्य शुरू हो गया है। लोगों की निजी संपत्तियों को हुए नुकसान और क्षतिग्रस्त घरों के लिए जल्द ही सहायता वितरित किया जाएगा। महत्वपूर्ण क्षेत्रों का बुनियादी ढांचा प्रभावित हुआ है और उसकी

अस्थायी बहाली का काम युद्धस्तर पर चल रहा है। प्रशासन द्वारा नुकसान के आकलन के साथ ही हरसंभव सहायता प्रदान की जाएगी।

श्री शाह ने कहा कि समीक्षा के जरिए व्यवस्था में सुधार ही हमें 'जीरो कैजुअल्टी अप्रोच' की दिशा में लेकर जा सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि हमारी सभी 'अर्ली वॉर्निंग एप्स' की पद्धतियों, उनकी सटीकता और उनकी जमीनी पहुंच का 'क्रिटिकल एनिलिसिस' होना चाहिए। मौसम विभाग व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को डेटा एनालिटिक्स और 'आर्टिफि शियल इंटेलिजेंस' के उपयोग से बादल फटने के कारणों का अध्ययन करना चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भारतीय खाद्य निगम पर्याप्त राशन की व्यवस्था करे। स्वास्थ्य और जल विभाग को जल आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति सचेत करते हुए श्री शाह ने सेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और वायु सेना के मेडिकल दस्तों की सहायता लेने का सुझाव दिया। ■

मेघालय में बोले केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर

बहुउद्देशीय संस्थानों में तब्दील हो रहे पैक्स

- ईस्ट खासी हिल्स ज़िले में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से किया संवाद
- मेघालय की प्रगति की सराहना करते हुए खासी हिल्स को विकास के एक मॉडल में बदलने का किया आह्वान

सहकार जागरण टीम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सहकारिता को ग्रामीण लोगों की आर्थिक आत्मनिर्भरता और विकसित भारत का आधार बना रही है। सरकार का विकसित भारत का दृष्टिकोण तभी साकार हो सकता है जब मेघालय जैसे दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों सहित प्रत्येक क्षेत्र देश के बाकी हिस्सों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रगति करें। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने इन विचारों को पूर्वोत्तर भारत के मेघालय राज्य में व्यक्त किया। पूर्वोत्तर में विकासात्मक पहलों को गति प्रदान करने के भारत सरकार के निरंतर प्रयासों के तहत राज्य के खासी हिल्स पहुंचे श्री गुर्जर ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), लखपति दीदी पहल, जल जीवन मिशन और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) के सुदृढ़ीकरण जैसी प्रमुख योजनाओं और अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने इन कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन की सराहना की और कहा कि नीति मूल्यांकन और वास्तविक समय में सुधार के लिए जमीनी स्तर पर लोगों की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। पूरे देश में सहकारी प्रगति पर संतोष जताते हुए श्री गुर्जर ने कहा कि पहले प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) मुख्य रूप से कृषि ऋण और उर्वरक वितरण जैसे कार्यों तक ही सीमित थे, लेकिन अब पैक्स कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन और ग्रामीण उद्यम को सहयोग देने वाले बहुउद्देशीय संस्थानों में तब्दील हो गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के दो वर्षों के भीतर दो लाख नए बहुउद्देशीय पैक्स बनाने का लक्ष्य रखा है, जो समुदाय-संचालित मॉडलों के माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करेंगे।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय (टीएसयू) की स्थापना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 'यह भारत का पहला सहकारी शिक्षा के लिए समर्पित विश्वविद्यालय है। यह सहकारी प्रबंधन, वित्त, कानून और ग्रामीण विकास में विशेष प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य ऐसे पेशेवरों का निर्माण करना है जो पूरे देश में सहकारी आंदोलन का नेतृत्व करेंगे।' टीएसयू भारत भर के विश्वविद्यालयों से संबद्ध होगा और सहकारी शिक्षा को मुख्यधारा के शिक्षाविदों में एकीकृत करेगा, विशेष रूप से आदिवासी और ग्रामीण युवाओं को लक्षित करेगा। उन्होंने प्रभावी केंद्र-राज्य समन्वय, डिजिटल निगरानी और धन के कुशल उपयोग के महत्व पर जोर दिया, साथ ही परियोजनाओं के समय पर और पारदर्शी क्रियान्वयन का आह्वान किया। श्री गुर्जर ने मेघालय के वरिष्ठ अधिकारियों, जिला प्रशासकों और विभागों के साथ केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की, जिसमें बुनियादी ढांचे, सामाजिक सशक्तीकरण और आजीविका आधारित कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया।

श्री गुर्जर ने मेघालय में हवाई अड्डों और रेलवे जैसी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए पहाड़ी इलाकों, वनों और सामुदायिक स्वामित्व के कारण भूमि अधिग्रहण में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार किया और कहा, 'लोकतंत्र में, हमें लोगों की चिंताओं को सुनना चाहिए। पर्यावरणीय संवेदनशीलता और स्थानीय भागीदारी को विकास के साथ-साथ चलना चाहिए।' जमीनी स्तर पर प्रगति के लिए मेघालय प्रशासन और नागरिक समाज के प्रयासों की सराहना करते हुए श्री गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर में हिंसा और उग्रवाद में उल्लेखनीय कमी आई है, और केंद्र से मजबूत वित्तीय सहायता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में यहां मंत्रियों की पहुंच बढ़ी है। उन्होंने खासी हिल्स को विकास के एक मॉडल में बदलने का आह्वान करते हुए कहा, 'इसे एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करें कि एक सच्चा विकसित भारत कैसा दिख सकता है। मुझे खासी हिल्स में प्रशासन द्वारा किए गए ईमानदार और समर्पित प्रयासों को देखकर सचमुच खुशी हो रही है। यह जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है।' ■

ग्रामीण समुदायों का सामर्थ्य बढ़ा रही सहकारिता

सहकारिता-आधारित सतत विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने, श्वेत क्रांति 2.0 को आगे बढ़ाने और नवाचारों पर जोर

सहकार जागरण टीम

सहकारिता के सामर्थ्य से किसानों, महिलाओं और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और ग्रामीण भारत के अर्थतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए सहकारिता मंत्रालय निरंतर पहल कर रहा है। सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने, श्वेत क्रांति 2.0 को आगे बढ़ाने और नवाचारों पर जोर दिया जा रहा है। सहकारिता-आधारित समावेशी विकास के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने बनास डेयरी के अध्यक्ष श्री शंकर चौधरी और सहकारिता मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गुजरात के एक रेगिस्तानी इलाके बनासकांठा में एशिया की सबसे बड़ी डेयरी के रूप में विख्यात बनास डेयरी और उसकी अत्याधुनिक इकाइयों का निरीक्षण किया। यह यात्रा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के संकल्प को पूरा करने के लिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के दूरदर्शी नेतृत्व में गुजरात में श्वेत क्रांति 2.0 को आगे बढ़ाने के लिए सहकारिता मंत्रालय के समर्पण को दर्शाती है।

सहकारिता-आधारित सतत विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए प्रतिनिधिमंडल ने सन 1969 में स्थापित बनास डेयरी प्लांट, आलू और आइसक्रीम प्लांट, थराद स्थित बनास सेव सॉयल लैब, उमंग मॉल स्टोर, कटारवा स्थित कैटल फीड प्लांट, अगाथल बायो-सीएनजी प्लांट, दामा स्थित सीमेन स्टेशन और बायो-सीएनजी प्लांट सहित कई सुविधाओं का अवलोकन किया। इस दौरान सहकारी प्रतिनिधियों ने सत्सान (तालाब) और जयगोल (वृक्षारोपण) पहल, बनास मेडिकल कॉलेज, बदरपुरा स्थित बनास फूड कॉम्प्लेक्स, जिसमें शहद, खाद्य तेल और अमूल आटा संयंत्र शामिल हैं और पालनपुर स्थित पनीर, मट्ठा पाउडर और यूएचटी संयंत्र का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। सहकारिता मंत्रालय के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल ने दो दिवसीय कार्यक्रम के तहत दूध मंडली और महिला दुग्ध उत्पादकों के प्रतिनिधियों सहित प्रमुख हितधारकों के साथ बैठक करके नवाचारों पर चर्चा की और सतत एवं समावेशी विकास के लिए एक रणनीतिक रोडमैप तैयार करने की पहल की गई। सहकारी प्रतिनिधिमंडल ने महिला संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से सहकारिता को मजबूती प्रदान किया।

ग्रामीण विकास, सामाजिक समानता और पर्यावरण संरक्षण के इंजन के रूप में सहकारी समितियों की परिवर्तनकारी क्षमता को पुष्ट करने वाली इस यात्रा के दौरान यह स्पष्टता से परिलक्षित हुआ कि कैसे बनास डेयरी और उसकी सहयोगी इकाइयां श्वेत क्रांति 2.0 को आगे बढ़ा रही हैं और पूरे देश में सहकारी-नेतृत्व वाली समृद्धि के लिए एक मानक स्थापित कर रही हैं। ■

बनास विजन

'हम अपने मूल्यों, सहकारी आंदोलन, महिला सशक्तीकरण, पुनर्योजी कृषि, नवाचार को सुदृढ़ करके, उत्पादक और टिकाऊ डेयरी फार्मिंग और वैश्विक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उत्पादों के साथ सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी बनने का प्रयास करेंगे; प्रौद्योगिकी के माध्यम से जीवन को समृद्ध बनाएंगे और सभी हितधारकों की खुशी के लिए 'डेयरी से परे' का विस्तार करेंगे, एक गुणवत्तापूर्ण संगठन, कार्य करने के लिए एक बेहतरीन स्थान बनकर और भारत को 'विश्व के लिए डेयरी' बनने में मदद करेंगे।'

विशेष आलेख

डॉ. एस. धर्मराज

राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025

सहकारिता बनेगी आधुनिक, समावेशी और भविष्य की आर्थिक शक्ति

सहकारी आंदोलन को देश की सामाजिक-आर्थिक उन्नति का मुख्य आधार बनाने और इसे अधिक समावेशी एवं सतत विकास के एक स्थाई स्तंभ के रूप में नई दिशा देने के लिए भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति घोषित की है। इसमें एक साहसिक और भविष्योन्मुखी ढांचे की संकल्पना के साथ सहकारिता को राष्ट्रीय विकास के केंद्र में रखा गया है, जो दो दशकों के लिए सहकारी विकास का आधार बनेगी। 'सहकार से समृद्धि' के चिंतन पर आधारित इस नीति का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद में सहकारिता का योगदान बढ़ाना, स्व-रोजगार सृजित करना और समाज के अंतिम छोर तक सेवाओं को पहुंचाना है। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप यह नीति सहकारी क्षेत्र का आधुनिकीकरण और व्यावसायिकीकरण करना चाहती है, जिससे इसे विकास के कुशल, पारदर्शी और जन-केंद्रित इंजन के रूप में कार्य करने के लिए सशक्त बनाया जा सके। नई नीति के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि भारत का कोई भी गांव सहकारी सेवाओं से अछूता न रहे। इसके लिए दो लाख बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (एमपैक्स) स्थापित करने का लक्ष्य है। ग्रामीण सेवा केंद्रों के रूप में सहकारी समितियां ऋण, खाद-बीज आदि उपलब्ध कराने के साथ ही मार्केटिंग में सहायता करेंगी और अन्य आवश्यक सेवाएं भी प्रदान करेंगी, जिससे ग्रामीण आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इस पहल के पूरक के रूप में आदर्श सहकारी गांवों का विकास किया जाएगा, जो सहकारी शासन, सतत आजीविका और युवा सहभागिता में सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रदर्शन करेंगे। सहकारिताएं सम्मान, समानता और स्थानीय नेतृत्व का साधन बनेंगी।

लचीले और समावेशी सहकारी भविष्य की ओर

समावेशिता नई सहकारिता नीति का मूल है। इस नीति में सहकारी आंदोलन के जरिए महिलाओं, युवाओं, छोटे किसानों और हाशिए पर पड़े जनजातीय समुदायों एवं अन्य लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नीतिगत रोडमैप प्रस्तुत किया गया है। इस नीति का लक्ष्य 50 करोड़ लोगों को सहकारिता के दायरे में लाने के साथ ही आर्थिक लोकतंत्र, सम्मान और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। यह नीति 'सहकारिताओं के बीच सहयोग' के स्थायी सिद्धांत के पुनरुत्थान का भी आह्वान करती है, जो सहकारी संस्थाओं के बीच तालमेल, साझा बुनियादी ढांचे और पारस्परिक विकास को बढ़ावा देता है। नई पॉलिसी सहकारी संस्थाओं को केवल आर्थिक इकाइयों के रूप में ही नहीं, बल्कि समग्र विकास के वाहक के रूप में पुनर्परिभाषित करती है और पर्यावरणीय स्थिरता, नैतिक व्यावसायिक आचरण और सामुदायिक प्रबंधन पर जोर देती है। आठ लाख से ज्यादा सहकारी समितियों की जानकारी एकत्रित करने वाला राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस देश भर में सहकारी पहलों की बेहतर निगरानी, योजना और कार्यान्वयन को सक्षम बनाएगा।

भारत की ग्रामीण और अर्ध-शहरी अर्थव्यवस्थाओं की गतिशील प्रकृति को स्वीकार करते हुए नई सहकारी नीति समितियों को स्वास्थ्य सेवा और डिजिटल सेवाओं जैसे उच्च-संभावित क्षेत्रों में बढ़ावा देती है। यह विस्तार सरलीकृत पंजीकरण प्रक्रियाओं, क्षेत्र-विशिष्ट प्रशिक्षण और भारत ब्रांड और सहकारी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसी पहलों के माध्यम से प्रतिस्पर्धी बाजारों तक पहुंच द्वारा समर्थित है। नई नीति के जरिए भारतीय बीज सहकारी समिति (बीबीएसएसएल), राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) और राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड (एनसीओएल) जैसी संस्थाएं कृषि, जैविक उत्पादों और मूल्यवर्धित वस्तुओं के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को और बढ़ावा देंगी। इस नीति में प्रस्तावित राष्ट्रीय सहकारी बैंक सहकारी समितियों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करेगा, जबकि एमपैक्स को बैंक मित्र के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया जाएगा।

सहकारी संघवाद के माध्यम से सहभागी कार्यान्वयन

नई नीति में सहकारी ढांचे को अधिक सशक्त और सहभागी बनाया गया है, जो सहकारी संघवाद की भावना को मजबूती प्रदान करता है। भारत की समृद्ध विरासत से प्रेरित यह नीति समुदाय-प्रबंधित जल प्रणालियों, सामूहिक खेती और ग्राम संघों जैसे सहयोग के पारंपरिक मॉडलों को पुनर्जीवित करती है। यह समावेशिता, नैतिकता और साझा समृद्धि पर आधारित एक सहकारी आंदोलन की परिकल्पना करती है। भारत की स्वदेशी सहकारी प्रथाओं को अपनाकर यह नीति विकास के ऐसे टिकाऊ मॉडल तैयार करेगी, जो आर्थिक विकास को पर्यावरणीय और सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ संतुलित करेंगे। ■

- सहायक प्राध्यापक, वैमनीकॉम, पुणे

एनसीयूआई ने नई दिल्ली में 72वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया, जिसमें 14 से 20 नवंबर 2025 तक प्रस्तावित इस कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए एनसीयूआई के मुख्य कार्यकारी डॉ. सुधीर महाजन की अध्यक्षता में एनसीएचएफ, एनएलसीएफ, नैफैक के प्रबंध निदेशक और इफको, कृभको, एनसीडीसी, एनसीओएल, एनसीईएल, बीबीएसएसएल, नेफेड, एनएफसीएसएफ, नैफकब, एनसीसीएफ और एनसीसीटी के वरिष्ठ अधिकारियों ने भागीदारी की।

एनसीसीई ने चीनी सहकारी क्षेत्र में नेतृत्व क्षमताओं को बढ़ाने और सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चीनी सहकारी समितियों के अध्यक्षों एवं निदेशकों के लिए तीन दिवसीय नेतृत्व विकास कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें प्रतिभागियों ने वरिष्ठ संकाय सदस्यों और विशेषज्ञों द्वारा नई सहकारी नीति, चीनी सहकारी समितियों के लिए विभिन्न योजनाओं और गन्ने की खेती की वैज्ञानिक तकनीकों, चीनी की मात्रा में सुधार, फसल की गुणवत्ता व कीट संरक्षण पर केंद्रित ज्ञानवर्धन किया।

एनसीसीई, नई दिल्ली में भारत की बहु-राज्यीय सहकारी समितियों के अध्यक्षों एवं निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली के प्रतिभागियों ने भाग लिया। एनसीयूआई अध्यक्ष श्री दिलीप संघाणी ने भी निदेशकों के साथ उनसे मुलाकात कर मार्गदर्शन किया।

भारत सरकार द्वारा सहकारी क्षेत्रों को बढ़ावा देने और ग्रामीण सशक्तीकरण के लिए प्रत्येक पंचायत तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करने में पैक्स की भूमिका पर त्रिपुरा सरकार ने अगरतला में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, जहां एनसीयूआई कार्यकारी निदेशक श्री रितेश दे ने 600 से अधिक पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामीण विकास कार्यकर्ताओं और राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों का मार्गदर्शन किया।

अमरेली जिला सहकारी संघ, गुजरात के 52 प्रतिभागियों के लिए राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केंद्र (एनसीसीई) ने नई दिल्ली में तीन दिवसीय नेतृत्व विकास कार्यक्रम (एलडीपी) का आयोजन किया, जहां उन्हें सहकारी मूल्यों एवं सिद्धांतों, डिजिटल परिवर्तन, नए व्यावसायिक विचारों, व्यवसाय प्रबंधन और सहकारी मार्केटिंग एवं ब्रांडिंग के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रशिक्षित किया गया।

एनसीसीई, नई दिल्ली के प्रशिक्षण कार्यक्रम में आए अमरेली जिला सहकारी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने इफको सदन में भ्रमण किया और इफको के सहकारिता मॉडल, 'सहकार से समृद्धि' जैसे विषयों के साथ-साथ कृषि एवं इफको के नैनो उर्वरकों के उपयोग पर सार्थक चर्चा की।

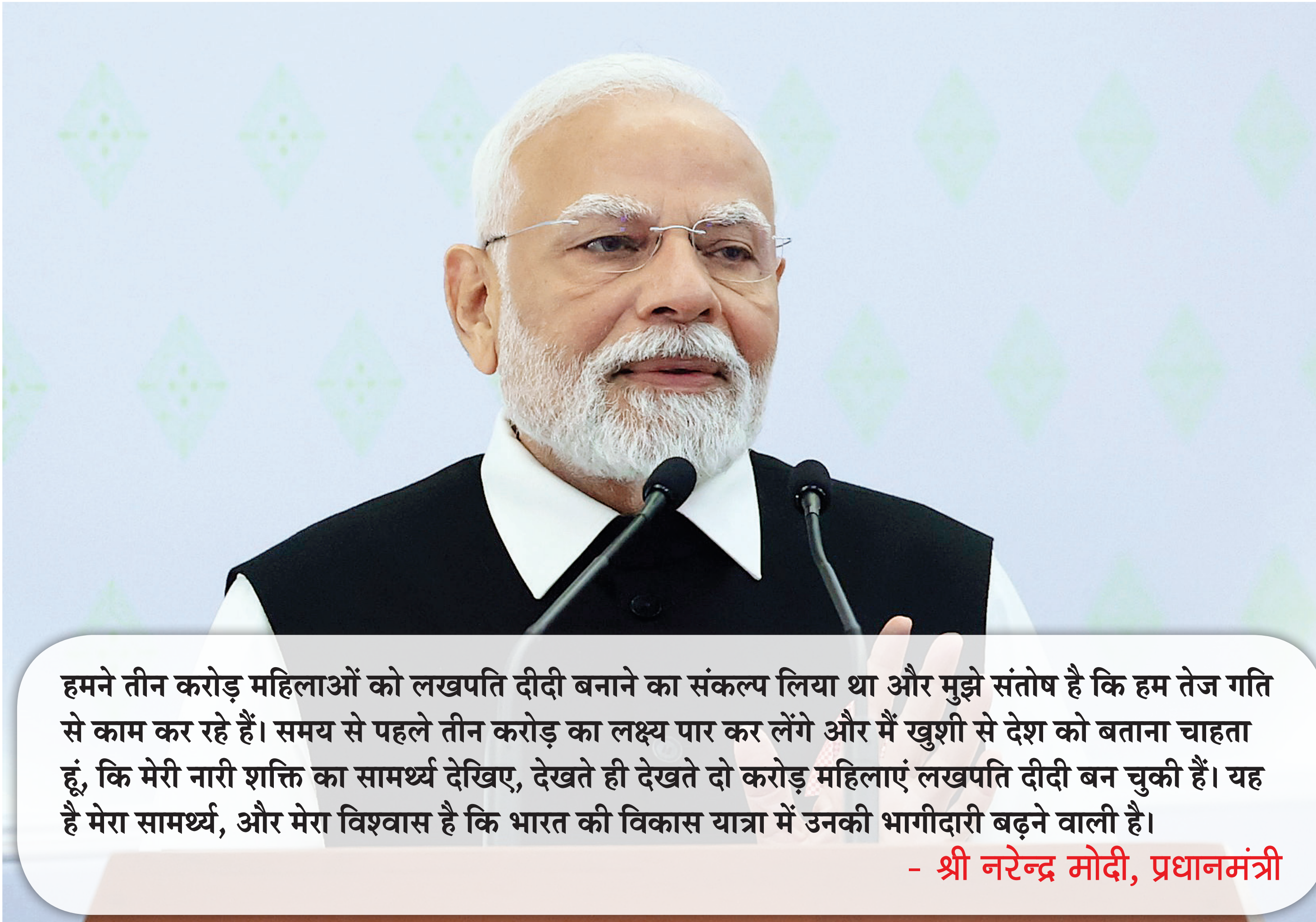

हमने तीन करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया था और मुझे संतोष है कि हम तेज गति से काम कर रहे हैं। समय से पहले तीन करोड़ का लक्ष्य पार कर लेंगे और मैं खुशी से देश को बताना चाहता हूं, कि मेरी नारी शक्ति का सामर्थ्य देखिए, देखते ही देखते दो करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। यह है मेरा सामर्थ्य, और मेरा विश्वास है कि भारत की विकास यात्रा में उनकी भागीदारी बढ़ने वाली है।

– श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

एनसीयूआई हाट, एनसीयूआई और कम प्रचलित सहकारी संस्थाओं के बीच नये आयाम स्थापित कर रहा है, जो उत्पांदों की बिक्री और प्रदर्शनी के लिए एक सामान्य प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है। अब एनसीयूआई हाट अपने नवीन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी *'सहकार से समृद्धि'* को साकार करने के लिए उपर्युक्त वातावरण का निर्माण कर रहा है।

CEAS-LMS Portal

कोऑपरेटिव एक्सटेंशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (CEAS-LMS) अपने तरह का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो सहकारी सदस्यों को सहकारिता से जुड़ी सेवाओं की जानकारी देता है। यह तीन चरण में काम करता है:

1. **LMS:** लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत पंजीकृत सदस्यों को प्रत्येक चरण की सहकार शिक्षा दी जाती है।
2. **QMS:** क्यूरी मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा मंच है जहां उपयोगकर्ता सहकारिता से जुड़े अपने मुद्दे रख सकते हैं, जिससे उन्हें तुरंत गुणवत्ता परक सलाह मिल सके।
3. **CRC:** कोऑपरेटिव रिर्सोस सेंटर सभी हितधारकों का प्लेटफार्म है, जिसके माध्यम से सहकारिता से जुड़े सभी सदस्य जानकारियों का आदान प्रदान कर सके।

https://ncuicoop.education/

नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के लिए राजीव शर्मा द्वारा प्रकाशित और एनसीयूआई प्रिंटिंग प्रेस, बी-81, सेक्टर-80, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में मुद्रित। संपादक : राजीव शर्मा

Postal Registration No: DLHIN/25/A0141
Published on 15.04.2024 Applied for Registration/ Exempted